शुक्रवार, 4 अप्रैल 2025

मौसम

तापमान	36 – 26
आर्द्रता	64%
सूर्योदय: 5:27	सूर्यास्त: 17:53

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आ सुव।।

www.samagya.in

समाज्ञा

स्थानीय खबरें पृष्ठ तीन, चार और पांच पर

कोलकाता, चैत्र शुक्लपक्ष सप्तमी, वि.स. 2082, पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

सुविचार : जिस इंसान को अपनी गलती पर पछतावा न हो तो समझिये आप उनको पहचान नहीं पाये।

माँ कालरात्रि –पृष्ठ 2

कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम मुहर

बंगाल में 25,753 टीचरों की नियुक्ति रद्द

- पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने जानबूझकर खामियों को छुपाया : उच्चतम न्यायालय
- शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को उनकी नौंकरी संबंधी अर्जियों पर तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया और कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया ''त्रुटिपूर्ण एवं दागदार'' थी। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 22 अप्रैल, 2024 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था और कहा गया था कि दागी अभ्यर्थियों को अपने को मिला ''वेतन/प्राप्त भुगतान'' वापस करना चाहिए। सीजेआई द्वारा लिखे गए 41 पन्ने के फैसले में कहा गया,''हमें उच्च न्यायालय के इस निर्देश में हस्तक्षेप करने का कोई वैध आधार या कारण नहीं मिला कि जहां भी दागी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए और उन्हें प्राप्त वेतन/भुगतान वापस करने के लिए कहा जाना चाहिए। चूंकि उनकी नियुक्तियां फर्जीवाड़े का परिणाम थीं, इसलिए यह धोखा देने के बराबर है। इसलिए, हमें इस निर्देश को बदलने का कोई औचित्य नहीं दिखता।'' शीर्ष अदालत ने कहा, ''ऐसे में, इन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द की जाती हैं। हालांकि, जो अभ्यर्थी पहले से ही कार्यरत हैं, उन्हें किए गए किसी भी भुगतान को वापस करने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएँगी। इसके अलावा, पूरी परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम शून्य घोषित होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्त नहीं किया जा सकता।'' न्यायालय ने ऐसे कर्मचारियों को राहत दी जो दागी अभ्यर्थियों की श्रेणी में नहीं थे और पहले अन्य राज्य विभागों या स्वायत्त निकायों में काम कर चुके थे। पीठ ने फैसले में कहा, ''ऐसे मामलों में, उनकी नियुक्तियां रद्द की जाती हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों को अपने पिछले विभागों या स्वायत्त निकायों में सेवा जारी रखने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा।'' पीठ ने फैसले में कहा, ''इसके अलावा, उनकी पिछली नियुक्ति की समाप्ति और उनके फिर से शामिल होने के बीच की अवधि को सेवा में विराम नहीं माना जाएगा। उनकी वरिष्ठता और अन्य अधिकार सुरक्षित रहेंगे, और वे वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे।'' फैसले में कहा गया कि लेकिन विवादित नियुक्ति के तहत नियोजित अवधि के दौरान राज्य या स्वायत्त निकायों द्वारा उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। अदालत ने कहा, ''इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो, इस अवधि में नियुक्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया जा सकता है।'' दिव्यांग अभ्यर्थियों के मुद्दे पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मानवीय आधार पर सोमा दास नामक अभ्यर्थी को पद पर बने रहने की अनुमति दी थी।

शीर्ष अदालत ने कहा, ''हम इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हम यह स्पष्ट करते हैं कि अन्य दिव्यांग अभ्यर्थी समान लाभ के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि यह कानूनी सिद्धांतों और कानून के शासन के विपरीत होगा। हालांकि, उनकी दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए, इन अभ्यर्थियों को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी और नयी चयन प्रक्रिया तथा नियुक्तियां पूरी होने तक उन्हें वेतन मिलेगा।'' अदालत ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को आयु में छूट और अन्य रियायतों के साथ नयी चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। पीठ ने कहा, ''इसी तरह, अन्य अभ्यर्थी जो विशेष रूप से दागी नहीं हैं, वे भी उचित आयु छूट के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। हमारी राय में, ऐसा निर्देश उचित और न्यायसंगत होगा, क्योंकि यह इन उम्मीदवारों को नयी चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देगा, जिसे अब रिक्तियों को भरने के लिए शुरू किया जाना चाहिए।'' शीर्ष अदालत ने हालांकि नयी चयन प्रक्रिया के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की।

न्यायपालिका का सम्मान, लेकिन शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती : ममता

- 25,753 शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर ममता ने जताई तीखी प्रतिक्रिया
- भाजपा पर बंगाल को बार-बार निशाना बनाने का लगाया आरोप

कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वह न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती हैं, लेकिन राज्य में 25,753 शिक्षकों की नियुक्तियों को अमान्य करार देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वह स्वीकार नहीं कर सकतीं। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 2016 में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा बंगाल में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,755 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को रद कर दिया और पूरी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सचिवालय नवान्न में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता में कहा, मैं न्यायपालिका और न्यायाधीशों का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। हालांकि ममता ने साथ ही कहा कि उनकी सरकार सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें निर्णय को स्वीकार करना होगा और कानूनी रूप से जो भी संभव होगा वह करेंगे। ममता ने कहा कि राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी इस मामले में जेल में हैं। सवाल किया कि एक व्यक्ति की गलती से कितने लोगों को सजा होगी। अदालत के फैसले के मद्देनजर भाजपा पर बरसते हुए ममता ने बंगाल को टार्गेट करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि बंगाल को बार-बार क्यों निशाना बनाया जा रहा है?

मैं भाजपा और केंद्र सरकार की मंशा जानती हूं। ममता ने सवाल किया कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में कितने भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया गया?

राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ बिल, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही बन जाएगा कानून

समर्थन में 128, विरोध में 95 वोट

नयी दिल्ली : वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को राज्यसभा ने भी हरी झंडी दे दी है। सभापति जगदीप धनखड़ के अनुसार, विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े और विपक्ष में 95 वोट पड़े। विपक्षी सदस्यों की ओर से सुझाए गए सभी संशोधन सदन ने खारिज कर दिए। वोटिंग से पहले, उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ ने मजाकिया लहजे में कहा कि 'मुझे वोट करने की दूर-दूर तक जरूरत नहीं है।' दरअसल विपक्ष के कुछ सदस्य उन्हें आसन पर बैठा देख हैरान हुए। तब सभापति ने उन्हें बताया कि उन्हें भी बिल पर वोट डालने का अधिकार है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पहले से लोकसभा से पारित हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उनका अनुमोदन मिलते ही यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा।इससे पहले, राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर को मिला कर 4 से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम नहीं होंगे। यह साफ तौर पर बताया जा चुका है।' उन्होंने कहा, 'वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और वैधानिक निकाय में केवल मुसलमानों को ही क्यों शामिल किया जाना चाहिए? अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई विवाद है, तो उस विवाद का समाधान कैसे होगा?'जब बीजेपी की ओर से डॉ। सुधांशु त्रिवेदी बोलने खड़े हुए तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। त्रिवेदी के कई वक्तव्यों के विरोध में नारेबाजी हुई। कांग्रेस के जयराम रमेश ने खड़े होकर आपत्ति जताई तो बचाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद उतर गए। शाह ने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और राजद के मनोज झा की टिप्पणियों का भी करारा जवाब दिया।

जब भाजपा सरकार हटेगी तब वक्फ बिल को संशोधन के जरिए कर देंगे रद्द : ममता

कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा से पारित किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का गुरुवार को एक बार फिर कड़ा विरोध करते हुए घोषणा की कि जब भाजपा सरकार केंद्र की सत्ता से हटेगी तब इस विधेयक को संशोधन के जरिए रद्द कर दिया जाएगा। केंद्र पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने के लिए लाया गया वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह से दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब मौजूदा सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। तब हम इस बिल को रद कर देंगे। ममता ने जोर देकर कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे सांसद वक्फ के लिए लड़ रहे हैं।

वक्फ़ विधेयक संविधान पर हमला और समाज में ध्रुवीकरण बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा: सोनिया

नयी दिल्ली : कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की प्रमुख सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को सरकार पर वक्फ़ संशोधन विधेयक को लोकसभा में मनमाने ढंग से पारित कराने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है तथा यह समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने संसद भवन परिसर में संपन्न सीपीपी की बैठक में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' संबंधी विधेयक, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, भारत के पड़ोसी देशों की राजनीतिक स्थिति, संसद में गतिरोध, विपक्ष के नेताओं को ''बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने'' और कई अन्य विषयों को लेकर सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखे प्रहार किए।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे

नयी दिल्ली : न्यायपालिका में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने पदभार ग्रहण करते ही सार्वजनिक तौर पर अपनी संपत्ति की घोषणा करने पर सहमति जताई है। पूर्ण पीठ की एक बैठक में शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्णय लिया और इसका विवरण उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर कहा गया है कि संपत्ति की घोषणा करना स्वैच्छिक आधार पर होगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना सहित उच्चतम न्यायालय के 30 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की घोषणा प्रस्तुत की है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक शीर्ष अदालत की पूर्ण पीठ ने यह संकल्प लिया है कि न्यायाधीशों को पदभार ग्रहण करते समय अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए, तथा जब भी कोई महत्वपूर्ण संपत्ति अर्जित की जाए, तो इसकी घोषणा प्रधान न्यायाधीश के समक्ष करनी चाहिए। वेबसाइट पर लिखा गया है, '' इसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा की गई घोषणाएं भी शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा स्वैच्छिक आधार पर की जाएगी।''

केंद्र ने ईपीएफओ में क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए दो नए सुधारों का किया ऐलान

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए दो नए सुधारों का ऐलान किया है। इससे क्लेम खारिज होने की शिकायतों को दूर करने में मदद मिलेगी। नए सुधारों के तहत ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम दाखिल करते समय चेक या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, जिससे 7.7 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ होगा। सरकार के अनुसार, इस आवश्यकता को शुरू में कुछ केवाईसी-अपडेट करने वाले सदस्यों के लिए पायलट आधार पर शुरू किया गया था। 28 मई, 2024 को इसके लॉन्च होने के बाद से, अब तक 1.7 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों को इसका लाभ मिल चुका है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब इस सुविधा को सभी सदस्यों के लिए लागू कर दिया है।

अमित शाह इस महीने बिहार, बंगाल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे

नयी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस महीने बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे और इसके बाद उनका नियमित तौर पर इन राज्यों में जाने का कार्यक्रम है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश करेगी जबकि अन्य दो राज्यों में वह अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों ने बताया कि शाह इन राज्यों में चुनाव तक लगभग हर महीने भाजपा की संगठनात्मक बैठकें आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि शाह के 14 और 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में तथा 30 अप्रैल को बिहार में रहने की संभावना है जबकि तमिलनाडु के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अमेरिका का शुल्क में वृद्धि का दांव 'उल्टा पड़ेगा', भारत पर प्रभाव कम: रघुराम राजन

नयी दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बृहस्पतिवार को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का लगभग 60 देशों पर लगाया गया जवाबी शुल्क का दांव 'उल्टा पड़ेगा' और भारत पर इसका प्रभाव 'कम' होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त मूल्य-आधारित शुल्क लगाने की घोषणा की है। उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ''हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अल्पावधि में, इसका सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह 'सेल्फ गोल' (खुद को नुकसान पहुंचाने) है। अन्य देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करें तो भारत के निर्यात पर किसी भी शुल्क का सीधा प्रभाव यह होगा कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ेंगी, इससे उनकी मांग कम होगी और फलस्वरूप भारत की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी।'' दस प्रतिशत का मूल शुल्क पांच अप्रैल से और 27 प्रतिशत नौ अप्रैल से प्रभावी होगा। कुछ क्षेत्रों को शुल्क से छूट दी गई है।

RED-X

B.W.P. PLY,
BOARDS& DOORS
'X' Factor that Makes A Difference
Stockist :
GULAB CHAND
LAL CHAND& Co.
9831114555
9874415555

सरकारी स्कूलों में 30 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश : ममता बनर्जी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि तापमान में बढ़ोतरी और उमस के कारण राज्य का शिक्षा विभाग 30 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करेगा। राज्य सचिवालय नबान्न में पत्रकारों से बातचीत में बनर्जी ने कहा कि मई के दूसरे सप्ताह से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने की सामान्य प्रथा के बजाय विभाग प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवकाश को पहले (30 अप्रैल से) घोषित करने संबंधी नोटिस जारी करेगा। उन्होंने कहा, शिक्षा विभाग इस संबंध में बाद में नोटिस जारी करेगा। शहर में बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले सप्ताह से पारा लगातार बढ़ रहा है। मौसम कार्यालय के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की उम्मीद है तथा निकट भविष्य में बारिश का कोई संभावना नहीं है।

रुपया शुरुआती नुकसान से उबरा, 22 पैसे चढ़कर 85.30 प्रति डॉलर पर

मुंबई : अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को रुपया अपने शुरुआती नुकसान से उबरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे के उछाल के साथ 85.30 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर बंद हुआ। ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा करीब 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने के बाद विश्व की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के कमजोर होने के कारण हुआ। शुरुआती कारोबार में घरेलू मुद्रा को झाटका लगा लेकिन जल्द ही इसने अपनी खोई जमीन फिर हासिल कर ली और दिन का अंत में यह सकारात्मक रुख के साथ बंद हुआ।

भारत और थाईलैंड ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन किया: प्रधानमंत्री मोदी

बिम्सटेक रात्रिभोज में मोदी और यूनुस एक साथ बैंठे

बैंकाक : भारत और थाईलैंड ने अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का बृहस्पतिवार को फैसला किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, समावेशी एवं नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं तथा विस्तारवाद के बजाय विकास की नीति में विश्वास करते हैं। मोदी ने यह टिप्पणी थाईलैंड की अपनी समकक्ष पैतोंगतार्न शिनावात्रा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की। इस वार्ता के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की। मोदी ने शिनावात्रा के साथ हुई बातचीत के बारे में कहा, हमने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और थाईलैंड के बीच पर्यटन, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया है। हमने आपसी व्यापार, निवेश और व्यवसायों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग (एमएसएमई), हथकरघा और हस्तशिल्प में सहयोग के लिए भी समझौते किए गए हैं। भारत और थाईलैंड ने रणनीतिक साझेदारी की स्थापना को लेकर एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल प्रौद्योगिकियों से लेकर संस्कृति तक के क्षेत्रों में पांच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। वार्ता के दौरान दोनों देशों की एजेंसियों ने मानव तस्करी और अवैध प्रवास से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई। थाईलैंड ने हाल ही में म्यांमा में फर्जी नौकरी गिरोह के चंगुल में फंसे 549 भारतीय नागरिकों को वापस लाने में भारत की मदद की थी। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने साइबर अपराध के शिकार भारतीयों की वापसी में सहयोग देने के लिए थाईलैंड सरकार का आभार व्यक्त किया। हमने इस बात पर सहमति जताई कि हमारी एजेंसियां मानव तस्करी और अवैध प्रवास से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगी। मोदी ने कहा कि भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण में थाईलैंड का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा, आज हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच 'रणनीतिक वार्ता' स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आसियान में एकता और केंद्रीयता का पूर्ण समर्थन करता है।

कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना चिंताजनक

यह पहली बार नहीं है कि देश की शीर्ष अदालत को कहना पड़ा कि कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई न्याय के नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन है। लेकिन ऐसी बलपूर्वक की गई कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बुलडोजर की नाइंसाफी नजर आई। कोर्ट का कहना था कि यह बुलडोजरी अन्याय केवल झुग्गियों व मकानों को ही नहीं गिरा रहा है, बल्कि यह कानून की उचित प्रक्रिया व अनुच्छेद 21 का भी अतिक्रमण है। जो हर नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। शीर्ष अदालत ने प्रयागराज में घरों को गिराए जाने को अमानवीय और अवैध बताते हुए शहरी विकास प्राधिकरण को प्रत्येक पीड़ित घर के मालिक को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान घटी उस घटना को तंत्र की संवेदनहीनता बताया जिसमें बुलडोजर द्वारा झोपड़ी गिराए जाने पर एक बालिका अपनी किताबें पकड़कर भाग रही थी। अदालत का कहना था कि तसवीर देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। साथ ही अधिकारियों की मनमानी और असंवेदशीलता को उजागर करती है। कहा गया कि अतिक्रमणकारियों को खुद की स्थिति को स्पष्ट करने का उचित अवसर दिए बिना बुलडोजर से उनके मकान या झोपड़ियों को ध्वस्त करना अन्याय जैसा ही है। जिससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रशासन का इरादा अनधिकृत निर्माण को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें सबक सिखाना लगता है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में शासन-प्रशासन कथित 'तत्काल न्याय' के बुलडोजर मॉडल को लागू करने में सबसे आगे रहा है। इस विवादास्पद कार्रवाई का बचाव करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कभी-कभी कुछ लोगों को उनकी समझ में आने वाली 'भाषा' में चीजों को समझाने की जरूरत होती है। जिसके मायने यह भी हैं कि ऐसे तत्वों को अदालतों द्वारा उन्हें दोषी या निर्दोष ठहराये जाने का इंतजार किए बिना ही दंडित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बीते साल नवंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर के लगातार इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये कई दिशा-निर्देश दिए थे। इसमें मकान आदि के ध्वस्तीकरण से पंद्रह दिन पहले कब्जाधारियों को सचेत करना भी शामिल था। अदालत ने तो यहां तक चेतावनी दी थी कि निर्देशों का अतिक्रमण करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत में बदलाव नहीं आया। इसमें दो राय नहीं कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के प्रति शून्य-सहिष्णुता का नजरिया जरूरी है। अवैध निर्माण हटाया जाना चाहिए, लेकिन सभी कायदे-कानूनों का पालन भी उतना ही जरूरी है। अदालत मानती रही है कि जल्दबाजी में बुलडोजर का इस्तेमाल असंवैधानिक है और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। प्रयागराज व महाराष्ट्र में कई जगह लोगों ने आरोप लगाया कि नोटिस देने के चौबीस घंटों में ही उनके मकान गिरा दिए गए। ऐसी ही कार्रवाई नागपुर हिंसा के बाद आरोपियों के घर गिराने में की गई। कहा गया कि लोगों को अपील करने का भी मौका नहीं दिया गया। वैसे यह नैसर्गिक न्याय की अवहेलना है कि एक कथित दोषी के कृत्यों की सजा उसके पूरे परिवार को दी जाती है। उस घर में उस व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं। यह विडंबना है कि नागपुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बैंच ने आरोपियों की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगायी थी, लेकिन जब तक आदेश पहुंचा तब तक स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर चुका था। वैसे हकीकत यह भी है कि कोई अवैध निर्माण रातोंरात खड़ा नहीं हो जाता। जब उसका निर्माण होता है तो स्थानीय प्रशासन की नजर उस पर क्यों नहीं जाती। एकाएक ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो जाती है कि उसे गिराने की तत्काल जरूरत पड़ती है। फिर तुरत-फुरत बुलडोजर चल जाता है। सवाल यह भी कि हर छोटे-बड़े, धनाढ्य वर्ग, प्रभावशाली नेताओं के अवैध निर्माण पर पीला पंजा क्यों नहीं चलता? निस्संदेह, बुलडोजर की गति राजाश्रय के संरक्षण में ही तेज होती है।

माता कालरात्रि की पूजा का महत्व

नवरात्रि के सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को काली मां भी कहा जाता है। माता कालरात्रि का रूप बहुत ही विकराल है क्योंकि माता दुर्गा का 7वां अवतार कालरात्रि पापियों का संहार करने के लिए धरती पर आती हैं। माता कालरात्रि की पूजा में रात की रानी का फूल चढ़ाना चाहिए। साथ ही कालरात्रि मां को गुड़, गुड़ से बनी चीजों या मालपुए का भोग लगाया जाता है। आइए, विस्तार से जानते हैं माता कालरात्रि कौन है और क्या है इनकी पूजा का महत्व।

आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के सातवें दिन को महासप्तमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि को मां दुर्गा के नौ अवतारों में बहुत ही क्रोधी देवी माना जाता है क्योंकि जब-जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, तो देवी कालरात्रि का अवतार लेकर पापियों का संहार करने के लिए आती हैं। देवी कालरात्रि को अंधकार की देवी भी कहा जाता है लेकिन देवी कालरात्रि केवल दुष्टों का ही संहार करती हैं। अपने भक्तों और अच्छे मनुष्यों पर देवी कालरात्रि की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी भक्त देवी कालरात्रि की पूजा करता है, उसे अकाल मृत्यु का खतरा नहीं रहता। आइए, जानते हैं नवरात्रि के सातवें दिन की देवी कालरात्रि की विशेष पूजा विधि, भोग और महत्व।

कालरात्रि माता कौन हैं

नवरात्रि का सातवां दिन कालरात्रि माता को समर्पित होता है। 'कालरात्रि' नाम का अर्थ है 'अंधेरी रात'। कालरात्रि क्रोध में विकराल रूप धारण कर लेती हैं। काले रंग और बिखरे बालों के साथ, वह अंधकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके गले में एक चमकदार मुंड माला है, जो बिजली जैसी दिखती है। कालरात्रि सभी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। वह अंधकार में विकराल रूप जरूर धारण करती है लेकिन उनके आगमन से दुष्टों का विनाश होता है और चारों ओर प्रकाश हो जाता है। मां कालरात्रि को देवी काली का रूप भी माना जाता है। देवी कालरात्रि पापियों का संहार करके उनका लहू पीती हैं।

माता कालरात्रि की पूजा का महत्व

माता कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के जीवन से भय का नाश होता है। साथ ही भक्त पराक्रमी और साहसी बनते हैं। कालरात्रि की पूजा करने से समस्याओं से लड़ने की अद्भुत क्षमता का विकास होता है। महासप्तमी पर माता कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। कालरात्रि की कृपा से भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश होता है और वे विजय पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं।

नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा विधि

नवरात्रि में 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद माता कालरात्रि की पूजा के लिए चौकी सजाएं। माता की तस्वीर पर काले रंग की चुन्नी चढ़ाएं। इसके बाद मां कालरात्रि को रोली, अक्षत, दीप और धूप अर्पित करें। इसके बाद माता कालरात्रि को रात रानी का फूल चढ़ाएं। फिर गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। इसके बाद माता कालरात्रि पाठ, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

माता कालरात्रि का भोग प्रसाद

माता कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। साथ ही माता कालरात्रि को मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। इससे कालरात्रि मां की कृपा आप पर बनी रहेगी। कालरात्रि मां को मीठे का भोग इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि क्रोधित माता को मीठा खिलाकर ही शांत और प्रसन्न किया जा सकता है।

विश्व रंगमंच दिवस और महिला कलाकार

डॉ.राम आह्लाद चौधरी
प्रोफेसर, कलकत्ता विश्वविद्यालय

विश्व रंगमंच दिवस की प्रासंगिकता और महत्ता पर जब-जब चर्चा होती है, तब-तब यही कहा जाता है कि रंगमंच सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, यह एक ऐसा मंच है, जिसके जरिये समाज के विभिन्न स्तरों पर सहजता के साथ पहुँचा जा सकता है। रंगमंच के जरिये समाज में जिस तरह वैज्ञानिकता बढ़ायी जा सकती है, ठीक उसी तरह सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजना भी संभव हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ पूरे विश्व में रंगमंच के जरिये संदेश देने के सम्बन्ध में विश्व रंगमंच दिवस मनाने की बात उठकर सामने आयी। जिन लोगों ने इस रंगमंच की महत्ता को गहरायी से समझने की कोशिश की, उन तमाम लोगों में ऐसे भी लोग थे, जो कलाकार नहीं थे। इसी से पता चलता है कि नये कलाकारों को कला की दुनिया से जोड़ना आवश्यक है तथा उन्हें प्रोत्साहित करना भी एक जरूरी कार्य है। दूसरी बात यह है कि संवाद को सही ढंग से स्थापित किया जा सकता है। रंगमंच के जरिये संवाद को गंभीर से गंभीर बनाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में जब गंभीर विषयों की चर्चा होती है, तब यह कहा जाता है कि गंभीरता के जरिये कोई काम संभव नहीं है, अधिकतर व्यक्ति गंभीर विषयों से बाहर रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि गंभीरता शायद कोई बीमारी हो गई है। इस संदर्भ में बातचीत आरंभ करने से पता चलता है; यह एक सामाजिक बीमारी है, जो नव-उदारीकरण के युग में उत्पन्न हुआ है। और यह बीमारी लाइलाज बन गई है। इस लाइलाज बीमारी को तोड़ना यानी खत्म करने का अभियान रंगमंच के जरिये संभव है। विज्ञान कहता है कि ज्यों-ज्यों समस्याएं बढ़ती हैं, उन समस्याओं को दूर करने का भी रास्ता मिलने लगता है। शायद रंगमंच को अभिव्यक्ति का मंच बनाने से समस्याएं कुछ हद तक कम हो सकती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए आगे आना जरूरी है। कहना यह आवश्यक है कि रंगमंच के जरिये नये कलाकारों को आगे लाने पर जोर देना होगा।

हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस दिन सौहार्दता के साथ नाटक और उसके मंचन में हिस्सा लेना आवश्यक है। यह आवश्यकता तभी पूरी हो सकती है, जब कलाकारों को सम्मान दिया जाए। इस उदेश्य से दुनिया के विभिन्न समस्याओं के जरिये रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस दिवस मनाने को लिए तथा कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए सांस्कृतिक सद्भाव पर विशेष जोर देना वर्तमान की मांग है। इस मांग को ध्यान में रखकर महिला कलाकारों को कला जगत में अधिकार के साथ स्थापना करने की दिशा में लॉस एंजिल्स महिला थिएटर महोत्सव को विश्व में ख्याति मिली है।

खासकर महिला कलाकारों को आगे बढ़ाने की दिशा में यह संस्था काफी काम करती है। इस साल भी इस संस्थान ने महोत्सव को सफल बनाया है। इस तरह के कार्यक्रम दुनिया के विभिन्न देशों में इस साल भी मनाये गये हैं।

लॉस एंजिल्स महिला थिएटर फेस्टिवल (एल ए डब्ल्यू टी एफ) ने हर साल लगभग सात सौ बहु-संस्कृति वाली महिलाओं को आगे बढ़ाया है । पिछले तैंतीस साल के सफर में इसने यह कृति बनायी है। जाहिर है कि पितृसत्तात्मक और पुरुष-प्रधान मनोरंजन उद्योग द्वारा महिला कलाकारों को अनदेखा किया जाता है। उनके काम के लिए सम्मानित होने और लाइव स्टेज पर एकल महिला शो करने के लिए भी जगह नहीं दी गई है। इस साल 32वें एल ए डब्ल्यू टी एफ का पुरस्कार समारोह 27 मार्च को बार्न्सडॉल गैलरी थिएटर में हुआ । सोलो फेस्टिवल परफॉर्मेंस 28-30 मार्च को नॉर्थ हॉलीवुड के थिएटर 68 आर्ट्स कॉम्प्लेक्स-द रोज़ली थिएटर में हुआ।

महिलाओं के लिए एल.ए. का सबसे लंबे समय से चलने वाला सालाना एकल उत्सव है, जिसे बहु-प्रतिभाशाली महोत्सव निर्देशक फे हॉसर-प्राइस ने संचालित किया। कई कलाकारों द्वारा मंच पर प्रस्तुत किए गए गीत और नृत्य के एक शानदार प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ, जिसमें 2025 के स्ट्रॉन्गार टुगेदर पर जोर दिया गया। कुछ लोगों को एकजुटता का यह भाव विडंबनापूर्ण लगा, क्योंकि यह एक-व्यक्ति शो का उत्सव है, लेकिन जो भी हो, यह चकाचौंध कलात्मक रूप से प्रस्तुत की गई थी और देखने में आनंददायक थी।

शाम के पुरस्कार समारोह के दौरान, अधिकांश भाग के लिए, तीनों एकल प्रदर्शन किए गए। अलग-अलग प्रस्तुतियों में, एशले गेल और वनिया इबर्गुएन ने शानदार नृत्यकला का प्रदर्शन किया, जिसे कुशलता से निष्पादित किया गया था। नंगे पांव, कामुक गेल फूलों के गुलदस्ते के साथ एक स्वप्निल टुकड़े के माध्यम से तैरती हुई प्रतीत हुईं। पुरस्कार विजेता इबर्गुएन ने एक पारिस्थितिक किनारे के साथ एक अलौकिक, जल-थीम वाला नृत्य प्रस्तुत किया । हूफ़र्स , करेन ए और क्लार्क की एकल उपस्थिति ने गीत और अभिनय पर जोर दिया।

मंच के पीछे लगे स्क्रीन पर दिखाए गए सिज़ल रीलों और ट्रेलरों के बीच, इन प्रदर्शनों और पुरस्कार समारोह की सह-मेजबानी मार्गरेट एवरी द्वारा एक सुसज्जित पोडियम से की गई, जिन्हें स्टीवन स्पीलबर्ग की 1985 की द कलर पर्पल में शुग की भूमिका निभाने के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था; 1973 की ब्लैक्सप्लॉइटेशन फिल्म हेल अप इन हार्लेम में फ्रेड विलियमसन के साथ सह-अभिनय किया था; और हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक टीवी श्रृंखला जीनियस में एमएलके की मां मामा किंग का किरदार निभाया था ।

सह-प्रस्तुतकर्ता टेड लैंग, जो टीवी की लोकप्रिय लव बोट सीरीज़ में इसहाक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं, के पास एक थिएस्पियन और बार्ड के रूप में एक मजबूत थिएटर पृष्ठभूमि भी है और उन्होंने रेनेसां मैन थिएटर अवार्ड जीता है। एवरी और लैंग, जिनके बीच लंबे समय से पेशेवर संबंध रहे हैं, ने कुछ हद तक अव्यवस्थित समारोह के दौरान हंसी-मज़ाक किया और उन्हें देखना बहुत मज़ेदार रहा, खासकर जब वे अपने संकेतों को याद करते थे, जैसे कि किसी पुरस्कार विजेता को वास्तव में पेश किए जाने से पहले मंच पर आमंत्रित करना और उसके वीडियो क्लिप दिखाए जाने से पहले।

एलए निवासी जूली किम को रेनबो अवार्ड से सम्मानित किया गया। पिछले साल, किम को एल ए डब्ल्यू टी एफ में नृत्य करना था, लेकिन वह अपने टखने में चोट लगने के कारण मंच पर नहीं पहुंच पाई और उनकी जगह जियॉन्ग चोई ने पुरस्कार लिया, जो पारंपरिक, रंगीन पोशाक पहने हुए कोरियाई नृत्य करने के लिए सियोल से आए थे। प्यूर्टो रिकान अभिनेत्री -निर्देशक-निर्माता-कार्यकर्ता और एलए के हीरो थिएटर की संस्थापक-निर्माता कलात्मक निदेशक, एलिसा बोकेनेग्रा को मावरिक अवार्ड मिला।

एल ए डब्ल्यू टी एफ के इंटीग्रिटी अवार्ड के लिए जुनीता जेनिंग्स के स्वीकृति भाषण में कुछ मंच और स्क्रीन इतिहास शामिल था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती मोशन पिक्चर जुनीता मूर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, जिनकी 1959 की इमिटेशन ऑफ लाइफ में ऑस्कर के लिए नामांकित भूमिका ने युवा जेनिंग्स को अभिनय करने के लिए प्रेरित किया-और दर्शक इससे बेहतर हुए।

जेनिंग्स प्रसिद्ध नीग्रो एनसेंबल कंपनी में शामिल हो गईं, सोप ओपेरा ऐज द वर्ल्ड टर्न्स में पहली अश्वेत अनुबंधित खिलाड़ी थीं, उन्होंने एचबीओ के लॉरेल एवेन्यू के लिए केबलएसीई पुरस्कार जीता, और ऑगस्ट विल्सन के किंग हेडली के निर्माण में उनकी भूमिका के लिए एनएएसीपी थिएटर पुरस्कार जीता।

डॉन डिडाविक को ब्रॉडवे, ऑफ-ब्रॉडवे और बड़े व छोटे पर्दे पर दशकों तक अभिनय करने के लिए इटरनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें 2000 की फिल्म एरिन ब्रोकोविच में जूलिया रॉबर्ट्स के साथ अभिनय भी शामिल है ।

इस साल का इनफिनिटी अवार्ड, जो मरणोपरांत किसी महिला प्रतिभा को दिया जाता है, जो आसमान में बड़े पर्दे पर उतरी हो, कुछ हद तक चौंका देने वाला था। यह आमतौर पर एक कलाकार को दिया जाता है, लेकिन 2025 में, इनफिनिटी अवार्ड और भी अधिक अनंत हो गया, क्योंकि इसे दो कलाकारों को दिया गया।

अभिनेत्री-निर्देशक नैन्सी चेरिल डेविस बेलामी के अलावा, जो 1980 के दशक की फिल्मों हॉलीवुड शफल, आई एम गोना गिट यू सक्का और 1993 की मेनस, मित्ज़ी गेनर, जो बड़े पर्दे की फ़िल्म म्यूज़िकल और टीवी स्पेशल के लिए जानी जाती हैं, उन्हें भी पुरस्कार दिया गया। एल ए डब्ल्यू टी एफ से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक असंभावित विकल्प प्रतीत होती हैं, जो आम तौर पर बहु-सांस्कृतिक महिलाओं के उत्थान पर केंद्रित है जो आम तौर पर बोर्ड पर एकल महिला अभिनय करती हैं। दर्शकों को दिवंगत मित्ज़ी की ओर से दो मरणोपरांत स्वीकृति भाषण सुनने पड़े, दूसरा भाषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया जिसे बहुत ही खास अतिथि के रूप में प्रचारित किया गया-जो, लेकिन निश्चित रूप से, ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में इस फ़िल्म इतिहासकार ने कभी नहीं सुना था और जिसने वर्षों तक गेनर के साथ काम किया था।

भारतीय रेल का नया कीर्तिमान, बीते वित्त वर्ष में बनाए 7,134 कोच

- **2014 से 2024 के बीच कोच उत्पादन का आंकड़ा 54,809 पहुंचा**
- **आम आदमी का ध्यान रखकर नॉन एसी कोचों के उत्पादन में वृद्धि**
- **कोच निर्माण में दुनिया का अग्रणी देश बनकर उभरा भारत**

नयी दिल्ली : भारतीय रेल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,134 कोचों का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह संख्या पिछले वर्ष 6,541 कोचों के उत्पादन की तुलना में करीब 9 प्रतिशत अधिक है। आम आदमी का ध्यान रखते हुए गैर वातानुकूलित कोचों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले वित्त वर्ष में 4,601 नॉन एसी कोच का उत्पादन हुआ। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय रेल की उत्पादन क्षमता में लगातार हो रही वृद्धि को दर्शाती है, जो बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। इससे रेल सेवाएं अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और कुशल बनेंगी। जिससे यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव मिलेगा।

भारतीय रेल की तीन कोच निर्माण इकाइयां हैं। जिसमें तमिलनाडु के चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आई.सी.एफ.), पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री (आर.सी.एफ.) और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एम.सी.एफ.) शामिल है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आई.सी.एफ.) ने वर्ष 2024-25 में पिछले उत्पादन रिकॉर्ड को तोड़ने हुए 3,007 कोच का उत्पादन किया है।

कोच निर्माण इकाइयाँ स्थान	कोच उत्पादन (2023-24)	कोच उत्पादन (2024-25)	कोच उत्पादन में वृद्धि
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आई.सी.एफ.), चेन्नई, तमिलनाडु	2,829	3,007	+178
रेल कोच फैक्ट्री (आर.सी.एफ.), कपूरथला, पंजाब	1,901	2,102	+201
मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एम.सी.एफ.) रायबरेली, उत्तर प्रदेश	1,684	2,025	+341

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय रेल ने कोच निर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। 2004 से 2014 के बीच प्रति वर्ष औसतन 3,300 कोच के करीब था। वहीं 2014 से 2024 के बीच कोच उत्पादन का आंकड़ा रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ 54,809 पहुंच गया, जिसका औसत 5,481 कोच रहा है। कोच निर्माण क्षेत्र में यह वृद्धि भारतीय रेल द्वारा आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में निर्णायक है।

इसका उद्देश्य घरेलू निर्माण क्षमता को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता को कम करना और रेलवे संरचना में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाना है। रेल कोच निर्माण में भारतीय रेल की यह उपलब्धि 'मेक इन इंडिया' पहल को नया आयाम देती है। साथ ही विश्व पटल पर भारत को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करती है।

कोच उत्पादन में भारतीय रेल की सफलता 'मेक इन इंडिया' पहल का हिस्सा है, जो रेल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एडवांस तकनीक से लैस आधुनिक कोच यात्रियों को ज्यादा आराम, अधिक स्थान और अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैंगे। इससे यात्रा का अनुभव और ज्यादा आरामदायक बन रहा है। इसके साथ ही उच्च उत्पादन क्षमता से ट्रेनों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

आज का पंचांग

कोलकाता : 4 अप्रैल, शुक्रवार, 2025, विक्रम सम्वत् 2082, चैत्र शुक्लपक्ष सप्तमी, 20:19 तक, नक्षत्र : मृगशीर्षा, 05:49 तक, योग : शोभना, 21:48 तक, सूर्योदय: 5:27, सूर्यास्त: 17:53, चन्द्रोदय : 10:08, चन्द्रास्त: 24:25, शक सम्वतः 1947 विश्वावसु, अमान्ता महीना, सूर्य राशि : मीन, चन्द्र राशि : मिथुन, राहू काल : 10:07 से 11:39

राशिफल

मेष : मेष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकते हैं और आपको ऑफिस में प्रशंसा मिलने से आपके सहकर्मी परेशान हो सकते हैं। दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है।

वृष : वृष राशि वालों के लिए आज का दिन संतोष और शांति का है। आपको राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे। शासन और सत्ता से जुड़ने का लाभ मिल सकता है।

मिथुन : मिथुन राशि वालों को पिता के आशीर्वाद और अधिकारियों की कृपा से कोई मूल्यवान वस्तु या संपत्ति मिल सकती है और आपका दिन काफी व्यस्तता से भरा होगा।

कर्क : कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है और आपको ग्रहों की शुभ दशा से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सिंह : सिंह राशि वालों को राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी और आपको हर मामले में भाग्य का साथ मिलेगा। संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे।

कन्या : कन्या राशि के लोगों के लिए दिन सफलता से भरा होगा और आपका हर कार्य सिद्ध होगा। अपने कार्यों में तेजी लाने से लाभ होगा। गुस्से पर काबू रखें।

तुला : तुला राशि वालों के लोगों को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की संभावना है। आपके लिए आय के नए स्रोत बनेंगे और धन लाभ होगा।

वृश्चिक : वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ के योग हैं और आपके धन सम्मान में वृद्धि होने से मन प्रसन्न होगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और प्रियजनों से मुलाकात होगी।

धनु : धनु राशि वालों को लाभ होगा और आपकी सभी योजनाएं सफल होंगी। घर के सामान पर धन खर्च होगा, आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। सावधान रहें और अपने काम पर फोकस करें।

मकर : कल आपकी रचनात्मकता निखरेगी, जो आपको घर के नवीकरण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी। शांतिपूर्ण घरेलू माहौल को बढ़ावा मिलेगा।

कुम्भ : कल आप संतुष्टि की भावना का अनुभव करेंगे क्योंकि आप अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

मीन : कल आप नींद की कमी के कारण सुस्ती और ध्यान केंद्रित करने में कमी का अनुभव कर सकते हैं, जो आपके लक्ष्यों की दिशा में आपकी प्रगति में बाधा बन सकता है।

वर्ग पहेली नं. 3052

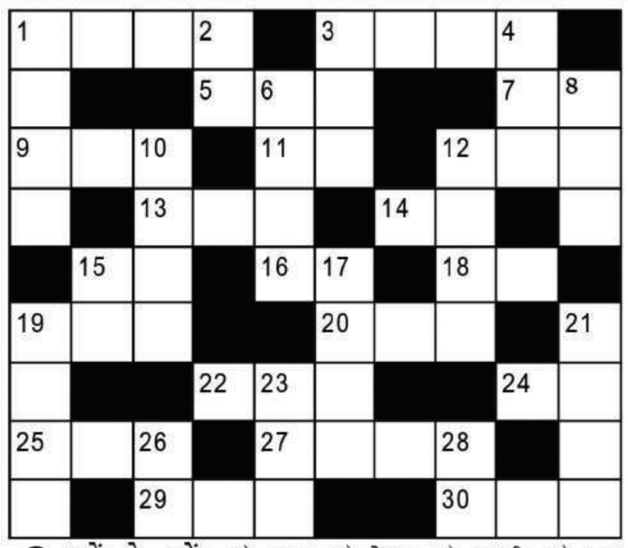

ऊपर से नीचे:- 1) खुल्लम खुल्ला, 2) शोरबा; पृथ्वी, 3) बंदर, 4) अज्ञानी, 6) पैसेवाला, 8) वासना, 10) चंगुल में लेना, 12) पैतृक धन का विभाग, 15) निकट भूतकाल, 17) जैन साधु, 19) मदमस्त चाल, 21) मृत्यु, 23) एक सिक्का, 26) एक ग्रह, 28) रग.

(उत्तर: अगले अंक में)

बायें से दायें:- 1) समुद्र, 3) वेश्या, 5) सामग्री, 7) ताप; गरमी, 9) इलज़ाम, 11) पतली लसदार थूक, 12) दैत्य, 13) मुसलमानी धर्मसूत्र, 14) एक प्रसिद्ध पेय, 15) अस्थि, 16) एक संख्या, 18) क़िस्मत, 19) पिघलना, 20) गुड्डी, 22) सूर्य, 24) प्रतीक्षा; मार्ग; विकल्प, 25) रहस्यमय; तलस्थ; अमिट, 27) व्यंजन; पक्का खाना, 29) किसी व्यक्ति के रंग-रूप आदि का विवरण, 30) गवाह.

पिछली पहेली का उत्तर

अ	म	न	■	■	अ	ड़ं	गा	■	प
ना	■	ज	म	घा	ट	■	ली	ट	र
व	ज़ी	र	■	प	ल	क	■	■	स्प
श्य	■	■	क	ला	■	व	फ़ा	दा	र
क	ला	कं	द	■	क	ल	■	ख़ि	■
■	प	■	र	स	द	■	बा	ल	म
क	र	भा	■	रा	म	दा	स	■	ध्य
स	वा	■	दा	स	■	मा	न	ना	■
म	ह	क	दा	र	■	द	■	ते	ज़ी

शब्दवेधी

सुडोकू-पहेली-3012

			6	5				1
8						2		
	7		9					
	9					7	5	
	3				8			
			1					
				4			3	
1								
2								

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरना आवश्यक है। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है।

••••

आड़ी और खड़ी में एवं 3-3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान जरूर रखें।

सूडोकू पहेली - 3011 का उत्तर

7	6	5	3	8	1	4	2	9
3	8	9	4	5	2	6	1	7
2	4	1	7	9	6	3	8	5
8	9	4	5	1	7	2	6	3
5	3	7	6	2	8	1	9	4
6	1	2	9	4	3	5	7	8
4	7	6	1	3	9	8	5	2
9	5	8	2	6	4	7	3	1
1	2	3	8	7	5	9	4	6

ममता ने नौकरी गंवाने वालों से धैर्य रखने की अपील की, कहा...

'मैं आपके साथ खड़ी हूं, कृपया उम्मीद न खोएं'

कोलकाता : ममता ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों के साथ एकजुटता जताते हुए उनसे धैर्य रखने की अपील की। ममता ने कहा– मैं आपके साथ खड़ी हूं। कृपया उम्मीद न खोएं। मैं समस्या के जल्द समाधान की कोशिश करूंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सात अप्रैल को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में उन सभी लोगों से मिलेंगी जिन्होंने न्यायालय के फैसले के बाद अपनी नौकरी खो दी है। ममता ने कहा– एसएससी एक स्वायत्त निकाय है। हमलोग उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यदि शीर्ष न्यायालय ने तीन महीने (नई चयन प्रक्रिया के लिए) का उल्लेख किया है, तो हमलोग फैसले के

अनुसार इस अवधि में प्रक्रिया शुरू कर देंगे। हमारे वकील इस मामले की समीक्षा करेंगे। हम मानवीय आधार पर उम्मीदवारों के साथ हैं। इस कदम के लिए, अगर भाजपा मुझे जेल भेजना चाहती है, तो भेज सकती है। मैं चाहती हूं कि नौकरी खोने वाले फिर से आवेदन करें।

❑ शिक्षकों को सैलरी लौटाने की जरूरत नहीं

ममता ने आगे कहा कि मैं खुद वकील हूं। मैं कानून की तकनीकियों को जानती हूं। मैंने एसएससी पर सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले के प्रत्येक लाइन को पढ़ लिया है, जो नौकरी कर रहे थे उन्हें वेतन वापस लौटाने की जरूरत नहीं है, ऐसा फैसला में लिखा हुआ है। कोर्ट के फैसले में लिखा है कि जिनकी नौकरी गई है उन्हें उम्र में छुट दी गई है और वे दोबारा नौकरी का आवेदन कर सकते हैं। ममता ने यह भी कहा कि यह मामला पहले हाल हो जाने के बाद एक लाख नई नौकरी के लिए आवेदन निकलेंगे।

❑ क्या भाजपा व माकपा बंगाल की शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करना चाहती है?

ममता ने कहा 'आज जो फैसला आया है यह भाजपा और माकपा का कराया–धराया है।' ममता ने कहा कि जिन लोगों की नौकरी गई है, उन्हें आत्मरक्षा का एक मौका मिलना चाहिए था। यह सिर्फ 25 हजार लोगों की बात नहीं है बल्कि कई लाख परिवार की बात है। ममता ने कहा कि नौकरी गंवाने वाले किसी भी शिक्षक के साथ कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और माकपा की होगी।

❑ यह केस विकास रंजन भट्टाचार्य ने किया था, उन्हें नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए : ममता

ममता ने भर्ती घोटाले में याचिकाकर्ता के वकील रहे वरिष्ठ माकपा नेता व राज्यसभा सदस्य विकास रंजन भट्टाचार्य पर भी निशाना साधा। ममता ने तंज कसते हुए कहा कि 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी लेने को लेकर दुनिया के सबसे महान वकील विकास रंजन बाबू को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं इसके लिए सिफारिश करूंगी। ममता ने यह भी कहा कि भाजपा और माकपा के लिए वार्निंग बेल बज चुका है। मैं भी बहुत सारे रिकार्ड निकालूंगी, उस समय कौन– कौन मंत्री थे। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी का नाम लिए बिना ममता ने कहा कि उनके जिले में किस–किसकी नौकरी हुई, सब रिकार्ड निकलवाऊंगी।

न्यायालय के फैसले से राज्यपाल बोस का रुख सही साबित हुआ : राजभवन

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक नियुक्तियों को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर बृहस्पतिवार को राजभवन ने कहा कि इस फैसले ने मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस के रुख को सही साबित कर दिया है।

राजभवन ने कहा कि राज्यपाल ने मामले में उभरती स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी देने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा।

चटर्जी को 23 जुलाई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित मामलों की जांच के सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया था।

राजभवन ने अपने कर्मचारियों को भेजे एक पत्र में कहा, उच्चतम न्यायालय के फैसले ने मामले में राज्यपाल के रुख को सही साबित कर दिया है।

पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं ने हजारों योग्य उम्मीदवारों के जीवन में तबाही मचा दी और वे नौकरियों से वंचित हो गए।

Notice

M/s. Steadfast Traders Pvt. Ltd. is the absolute legal & recorded owner of Total Land in nature 'Sali' measuring an areas 597.77 Decimals out of 413 Decimals land Mutated and 366 Decimals land converted as 'Karkhana' (Factory) in Mouza-Motinala, J.L. No. 24, under L.R. Dag Nos. 347, 348, 350, 351, 352, 353, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 & 482, L.R. Khatian No. 895, within the limits of Sarat Chandra Gram Panchayet and Mouza- Chakkamala, J.L. No. 23, under L.R. Dag No. 927, L.R. Khatian No. 520/2, within the limits of Orphuli Gram Panchayet, both under P.S.- Bagnan, Dist.- Howrah, Pin- 711303, State- West Bengal by way of 19 nos. registered Deed of Sale vide Nos. 5962, 5969, 5971, 5972, 5973, 5974, 5975, 5976 & 5977 all of 2022 and registered Deed of Sale vide Nos. 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3043, 3044, 3045 & 3054 all of 2023 and all were registered at ADSR-Bagnan.

The mother/Chain Deeds related to the said property are Deed vide nos. 4341, 4993, 5007, 5008, 5358, 4946, 4991, 4997, 4999, 4945, 4942, 4943, 4994, 4992, 4990 & 5088 all of 2022 & Deed no. 2336 of 1986 and all were registered at ADSR-Bagnan.

On 08.01.2025, The Company Director Mr.Hemant Lunia was traveling from his home to office at 16, Strand Road, Kolkata-700001, the aforesaid Original registered mother Deeds were lost from his custody. The Director, Sri Hemant Lunia lodge a complaint at New Alipur P.S. vide GDE no. 1888 dt 27.03.25 stating the above said fact. If any person found the said Deed please contact us at our address Diamond Heritage Building 16,Stand Road 14th floor unit no.1403 kolkata- 700001 and ph. No - 9830062111

पूर्व रेलवे

खुली निविदा सूचना सं. 01–एसडीएसटीई–एएसएन–2025–26, दिनांक 02.04.2025, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, पिन–713301 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। **कार्य का नाम/स्थान:** आसनसोल मंडल–निम्नलिखित के सिलसिले में सिग्नल एवं टेलीकम कार्य (1) शंकरपुर–जसीडीह के बीच किमी 318/1-3 (के.एम. 318.059) में एलसी गेट नं. 28 स्पे./ई के स्थान में एलएचएस का निर्माण, (2) ए. एस. कॉर्ड लाइन में कचूजोर–सिउड़ी के बीच किमी 47/5-7 पर एलसी नं. 18/सी/ई को बंद करने के स्थान में एलसी नं. 18/सी/ई से निकटवर्ती एलएचएस 19 तक कनेक्टिंग रोड का प्रावधान, (3) आसनसोल–खाना शाखा में कालीपहाड़ी–दामोदर के बीच सहायक कार्यों के साथ ब्रिज नं. 2 डीके की रिगर्डरिंग। **निविदा मूल्य:** रु. 55,30,702.79, **बयाना राशि:** रु. 1,10,600/–, **कार्य की समापन अवधि:** एलओए जारी करने की तिथि से 180 दिन। **निविदा बंद होने की तिथि और समय:** 28.04.2025 को 14.00 बजे। **वेबसाइट का विवरण: http://www.ireps.gov.in/**

ASN-07/2025-26

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहां देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

मेट्रो रेलवे, कोलकाता

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनकी ओर से कार्य करते हुए, **मु.सि.एवं दू.इं.**, मेट्रो रेलवे, कोलकाता खुली ई–निविदा के लिए ई–निविदाएँ आमंत्रित करता है जो 05.05.2025 **को** 15.30 **बजे** खुलेगी। निविदा के विरुद्ध मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और प्राप्त किसी भी मैनुअल प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया जाएगा। **कार्य का नाम** : मेट्रो रेलवे, कोलकाता की ब्लू लाइन में टेलीकम सब–सिस्टम के लिए यूपीएस पावर सप्लाई एवं केबल ट्रे का प्रावधान। **निविदा मूल्य** : रु.13,27,02,312.64, **पेशगी रकम** : रु. 8,13,500/–, **निविदा कागजातों के मूल्य** : रु.0 (शून्य)। **कार्य समाप्ति अवधि** : 6 माह। निविदा (टेंडर) को वेबसाइट **https://www.ireps.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदाकर्ता/बोली लगाने वाले के पास क्लास–III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र अवश्य होना चाहिए एवं आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। ई–टेंडरिंग पर केवल पंजीकृत निविदाकर्ता/बोली लगाने वाले ही भाग ले सकते हैं। सभी संबंधित कागजात ई–टेंडर में भाग लेते समय अपलोड होना चाहिए।

खोली टेंडर सूचना सं.: सं व दू/कार्य/09–2025

हमें यहाँ देखें: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने ममता के इस्तीफे की मांग की

❑ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने शिक्षकों की दुर्दशा के लिए ममता को ठहराया जिम्मेदार

❑ मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी लेने और तत्काल इस्तीफे की मांग की

कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को बंगाल में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,755 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित किए जाने के बाद भाजपा की प्रदेश इकाई ने इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री डा सुकांत मजूमदार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बंगाल में शिक्षक भर्ती में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी राज्य की विफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। उच्चतम न्यायालय के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासन में कैसे बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की योग्यता को पैसे के बदले बेचा गया। मजूमदार ने कहा, मैं नाकाम मुख्यमंत्री से इस भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी लेने और उनके तत्काल इस्तीफे की मांग करता हूं। अब और माफी नहीं।

इस पर ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या भाजपा चाहती है कि बंगाल की शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाए? ममता ने कहा कि बंगाल के तो पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में हैं, भाजपा बताए कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में भाजपा के कितने नेता गिरफ्तार हुए?

दूसरी ओर, मजूमदार ने एक वीडियो संदेश में, उन योग्य उम्मीदवारों के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की, जिन्होंने अपने कौशल और योग्यता का उपयोग करके नौकरी पाई, लेकिन ममता बनर्जी सरकार द्वारा पूरी भर्ती प्रक्रिया के भ्रष्ट संचालन के कारण पीड़ित बन गए। मजूमदार ने कहा कि भ्रष्ट ममता बनर्जी सरकार को राज्य के लोगों, विशेष रूप से योग्य शिक्षकों के परिवारों को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

मालूम हो कि शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बंगाल में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,755 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया और उनकी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण करार दिया।

शुभेंदु ने ममता का इस्तीफा मांगा

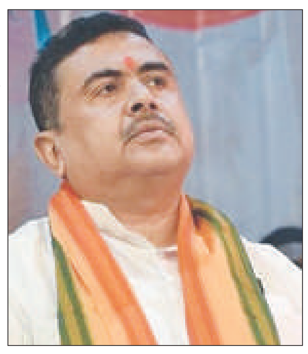

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य करार दिए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। शुभेंदु ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री को नियुक्तियों के अमान्य होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनकी पार्टी हजारों योग्य उम्मीदवारों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। शुभेंदु ने कहा, हम इस मामले में मुख्यमंत्री की संलिप्तता के लिए उनके इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, उच्चतम न्यायालय ने एसएससी (स्कूल शिक्षा आयोग) को योग्य और अयोग्य शिक्षकों के बीच अंतर करने के लिए बार–बार समय दिया। कैबिनेट द्वारा पांच मई, 2022 को अवैध रूप से अतिरिक्त पदों का सृजन किए जाने के बाद, मैं एसएससी कार्यालय पहुंचा और आयोग से योग्य व अयोग्य शिक्षकों की सूची तैयार करके अदालत में जमा करने की मांग की। लेकिन आयोग ने इसमें ढिलाई बरती। शुभेंदु ने कहा, हमने आयोग से कहा था कि अगर यह काम तत्काल नहीं किया गया, तो जिन लोगों को सही तरीके से नौकरी मिली है, वे मुश्किल में पड़ जाएंगे और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। शुभेंदु ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पर उनके कार्यकाल के दौरान एसएससी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को समाप्त करने का भी आरोप लगाया।

भ्रष्टाचार से घिरी भर्ती प्रक्रिया में अच्छे और बुरे का चयन संभव नहीं : विकास रंजन भट्टाचार्य

कोलकाता, समाज्ञा : पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगभग 26 हजार शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी गई है। 2016 के पैनल में जिन उम्मीदवारों को नौकरी मिली थी, वे अब बेरोजगार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि समग्र भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी। नौकरी गंवाने वाले शिक्षक प्रताप राय चौधरी ने कहा, हमारे सामने केवल एक रास्ता बचा है, और वह है मौत का रास्ता। यह रास्ता राज्य की विपक्षी पार्टी, विकासरंजन भट्टाचार्य और फिरदौस शमिम ने देखा था। इन लोगों ने पूरे पैनल को रद्द करने की कोशिश

की। वे जानते थे कि सभी योग्य नहीं हैं, लेकिन सभी अयोग्य भी नहीं हैं। उन्होंने सीपीएम को राज्य में फिर से प्रासंगिक बनाने के लिए यह कदम उठाया।

वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर कुछ फल सड़ गए हैं, तो प्राकृतिक कारणों से सभी को रद्द करना पड़ता है। यह बताने की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है कि कौन योग्य है और कौन जब कोई प्रक्रिया भ्रष्टाचार से घिर जाती है, तो उस प्रक्रिया में अच्छे और बुरे का चुनाव करना संभव नहीं होता। कानून को सर्वोपरि रखना चाहिए।

गौरतलब है कि 2016 के एसएससी शिक्षक भर्ती पैनल को कोलकाता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने तीन महीने के अंदर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार अयोग्य उम्मीदवारों का विवरण देने में विफल रही : शिक्षिका

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की शिक्षिका सोमा दास ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार और स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) अयोग्य उम्मीदवारों की कुल संख्या के बारे में न्यायपालिका के समक्ष सटीक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहे।दास के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने उनकी नियुक्ति अमान्य घोषित नहीं की। उच्चतम

न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित करते हुए उनकी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण करार दिया। हालांकि, उसने गंभीर बीमारियों से पीड़ित दास जैसे कर्मचारियों को मानवीय आधार पर छूट दी और कहा कि वे नौकरी में बने रहेंगे। कैंसर से पीड़ित दास ने कहा, 'एसएससी और राज्य सरकार के पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान कथित तौर पर अनुचित तरीकों से नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों की सही संख्या के बारे में उचित विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण आज की स्थिति उत्पन्न हुई।' उन्होंने कहा, 'मैं भी इस मामले की कई सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थी और मैंने देखा कि किस तरह न्यायाधीशों ने योग्य उम्मीदवारों की नौकरी बचाने की कोशिश की थी।' दास ने आरोप लगाया, 'राज्य के प्राधिकारी योग्य उम्मीदवारों का पक्ष समग्र रूप से प्रस्तुत करने में विफल रहे।' उन्होंने कहा कि वह उनके मामले को अलग नजरिये से देखने के लिए शीर्ष अदालत की आभारी हैं। दास ने कहा, 'पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय और अब उच्चतम न्यायालय ने मेरी स्थिति को एक अलग नजरिये से देखा। मैं इसके लिए उनका आभार जताती हूं।' हालांकि, उन्होंने कहा, 'मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है, जिन्होंने बिना किसी गलती के अपनी नौकरी गंवा दी।'

सियालदह मंडल में ट्रैक रखरखाव कार्य के लिए ट्रेनों का नियंत्रण व्यवस्था

प्वाइंट संख्या 235B/236A के परिवर्तन के लिए, दमदम जंक्शन स्टेशन सीमा पर अप/सीसीआर/लाइन पर 05.04.2025 (शनिवार) के 23.40 बजे से 06.04.2025 (रविवार) के 06.40 बजे तक 07 घंटे के लिए यातायात ब्लॉक की आवश्यकता होगी। परिणामस्वरूप, निम्नलिखित ट्रेनों को निम्नानुसार नियंत्रित किया जाएगा: - • **दिनांक 05.04.2025 (शनिवार) को रद्द ट्रेनें :** सियालदह - डानकुनी जं. : अप 32249/ डाउन 32252. • **दिनांक 06.04.2025 (रविवार) को रद्द ट्रेनें:** सियालदह - हाबरा: अप 33651/ डाउन 33652, सियालदह - बनगांव: अप 33813/ डाउन 33822, सियालदह - डानकुनी: अप 32211, 32213, 32215, 32217/ डाउन 32212, 32214, 32216, 32218. • **मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का पुनर्निर्धारण: 22202 डाउन पुरी - सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस [जेसीओ: 05.04.2025 (शनिवार)]** 3 घंटे के लिए पुनर्निर्धारित की जाएगी यानी पुरी से 19:25 बजे के बजाय 22:25 बजे रवाना होगी। • **मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन: i) 13148 डाउन न्यू कूचबिहार-सियालदह उत्तरबंगा एक्सप्रेस [जेसीओ: 05.04.2025 (शनिवार)]** को बैण्डेल जंक्शन के मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। -नैहाटी जं. - दम दम जं. डानकुनी के बजाय - दम दम जं. और बेलघरिया में रुकेंगे, **ii) 12344 डाउन हल्दीबाड़ी - सियालदह दार्जिलिंग मेल [जेसीओ: 05.04.2025 (शनिवार)]** नैहाटी जं. - दमदम जं. डानकुनी-दम दम जं. के स्थान पर को बैण्डेल जंक्शन के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा, **iii) 12378 डाउन न्यू अलीपुरद्वार - सियालदह पदातिक एक्सप्रेस [जेसीओ: 05.04.2025 (शनिवार)]** नैहाटी जं. - दम दम जं. डानकुनी के बजाय - दम दम जं. को बैण्डेल जंक्शन के मार्ग डायवर्ट किया जाएगा -, ब्लॉक अवधि के दौरान रेल सेवाएं विलंबित हो सकती हैं। असुविधा के लिए खेद हैं।

मंडल रेल प्रबंधक/सियालदह

पूर्व रेलवे

हमें अनुसरण करें : @EasternRailway @ easternrailwayheadquarter

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा भाजयुमो

❑ भाजपा की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में किया विरोध प्रदर्शन

कोलकाता : बंगाल में 25,753 शिक्षकों की नियुक्तियों को गुरुवार को अमान्य करार दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में विपक्षी भाजपा ने ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। फैसला आने के तुरंत बाद भाजपा की युवा इकाई भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने दोपहर में कोलकाता में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष डा इंद्रनील खान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे व गिरफ्तारी की मांग पर कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू के पास एकत्रित होकर मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर दिया। हाथों में तख्तियां व पोस्टर लिए

कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार व तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान टायर जलाकर भी विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन के चलते व्यस्त सेंट्रल एवेन्यू पर यातायात भी कुछ देर तक बाधित रही।

इधर, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता के इस्तीफे व गिरफ्त–ारी की मांग पर राज्य में पार्टी द्वारा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को पूरे राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सुवेंदु ने कहा कि रामनवमी के बाद बड़ा आंदोलन होगा। राज्य सचिवालय नवान्न घेराव अभियान भी होगा। हालांकि इसकी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।

प्रधानाध्यापकों ने कहा-एक साथ इतने सारे शिक्षकों की नौकरी चले जाने से स्कूल चलाना हो जाएगा असंभव

परीक्षा की तैयारी से लेकर प्रशासनिक कार्य तक सभी क्षेत्रों में होंगी समस्याएं

कोलकाता, समाज्ञा

कई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का कहना है कि एक साथ इतने सारे शिक्षकों की नौकरी चले जाने से स्कूल चलाना असंभव हो जाएगा। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। यदि इतने लंबे समय से अध्यापन कर रहे लोग भी इस बार अपनी नौकरी खो देंगे तो जिले की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी।

एक अधिकारी के अनुसार परीक्षा की तैयारी से लेकर प्रशासनिक कार्य और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक सभी क्षेत्रों में समस्याएं होंगी। यदि हम शीघ्र भर्ती नहीं करेंगे तो यह एक बड़ी समस्या होगी। मुर्शिदाबाद के फरक्का स्थित अर्जुनपुर हाई स्कूल के 60 शिक्षकों में से 36 अपनी नौकरी खो चुके हैं। प्रधानाध्यापक ने कहा कि अब 24 शिक्षकों द्वारा स्कूल में हजारों छात्रों को पढ़ाना कैसे संभव है? दक्षिण दिनाजपुर जिला प्रशासन सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिले में कम से कम 500 शिक्षकों की नौकरियां रद कर दी गई हैं। दक्षिण 24 परगना के कुलतली विधानसभा क्षेत्र के जामताला भगवानचंद्र हाई स्कूल के 10 और शिक्षकों की नौकरी रद कर दी गई। स्कूल के प्रधानाध्यापक शांतनु घोषाल के अनुसार जिन लोगों की नौकरी चली गयी उनमें से अधिकांश गणित और विज्ञान के शिक्षक थे। प्रधानाध्यापक सवाल उठा रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति में कक्षा में ये विषय कैसे पढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 11 शिक्षक रोते हुए स्कूल से चले गए। इस बार स्कूल में विज्ञान विषय कैसे पढ़ाया जाएगा? इसके अलावा स्कूल में कक्षा 5 से 10 तक की परीक्षाएं चल रही हैं। स्कूल में लगभग तीन हजार छात्र हैं। मैं स्कूल कैसे चलाऊंगा? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 2016 एसएससी पैनल में शामिल लगभग 26,000 लोगों की नौकरियां रद कर दीं।

विकास भवन में टीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवारों का जोरदार प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग तेज

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य में 26 हजार नौकरी रद्द होने के बाद विकास भवन के सामने 2022 टीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवारों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक ही झटके में 25,752 नौकरियां रद्द हो गई, जब कोर्ट ने 2016 के एसएससी पैनल को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद विधान–नगर स्थित विकास भवन के सामने उम्मीदवारों ने सरकार से जल्द नियुक्ति की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 50 हजार पदों पर शिक्षक की नियुक्ति की जाए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का–मुक्की हुई, और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। 2022 प्राथमिक टीईटी पास और डीएलएड एक्य मंच ने गुरुवार को विकास भवन पर आंदोलन का आह्वान किया था। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से प्रदर्शनकारियों को भवन से पहले ही रोक लिया, जिसके बाद उनके बीच तीखी बहस हुई। स्थिति तेजी से बिगड़ी और पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खींचकर हटाना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, 2016 एसएससी पैनल में शामिल लगभग 26 हजार लोगों की नौकरियां रद्द होने से शहीद मिनार के पास हताश और निराश लोग अपने भविष्य को लेकर दिखे चिंतित।

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आ सुव।।

www.samagya.in

समाज्ञा

NEWS PAPER ADVERTISING SOLUTION

▪ MATRIMONIAL ▪ PROPERTY ▪ RECRUITMENT

▪ EDUCATION ▪ NAME CHANGE ▪ PUBLIC NOTICE

▪ OBITUARY ▪ REMEMBRANCE ▪ DISPLAY

TO AD IN SAMAGYA PLEASE CONTACT

samagyaadvt@gmail.com | samagya.in

81, Chintamani Dey Road, Howrah 711 101, Mobile: 70444 44522

रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, यह सुनिश्चित करे पश्चिम बंगाल सरकार : राज्यपाल

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाना सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए। एक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई। बोस ने सरकार को किसी भी अप्रिय घटना रोकने के लिए पर्याप्त बल तैनात करने का भी निर्देश दिया। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्सव में किसी भी तरह से बाधा न आए, राज्यपाल ने राज्य

सरकार को सख्त सलाह दी है कि वह पूरे राज्य में रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए।' इसमें कहा गया है, 'राज्य सरकार को यह सलाह भी दी गई है कि वह राज्य के किसी भी हिस्से में किसी भी अप्रिय घटना के बारे में राजभवन को तत्काल सूचित करे।' रामनवमी छह अप्रैल को मनाई जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सभी समुदायों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान दिए बिना रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं। भाजपा पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए बनर्जी ने इसे एक जुमला संगठन बताया आर कहा कि इसका एकमात्र एजेंडा देश को धर्म के आधार पर बांटना है। बनर्जी ने बुधवार को राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, मैं सभी समुदायों से रामनवमी के दौरान शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील करती हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप किसी भी दंगे में शामिल न हों... याद रखें, यह उनकी योजना है। पश्चिम बंगाल में हम रामकृष्ण, विवेकानंद की शिक्षाओं का पालन करते हैं, न कि जुमला पार्टी की।' उन्होंने कहा, याद रखें कि धर्म व्यक्ति का होता है, लेकिन त्योहार सभी के लिए होते हैं। सिख कृपाण लेकर रैलियां निकालते हैं - आप भी रैलियां निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पुलिस के प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए और परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए। बनर्जी ने कहा कि वह नौ अप्रैल को जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने संबंधी अफवाह का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा कि इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बनर्जी ने कहा, 'उन्होंने अफवाह फैलाई कि मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे डिजिटल मीडिया का उपयोग करके ऐसी फर्जी बातें फैला रहे हैं। हमने एफआईआर दर्ज कराई है।'

चैती छठ पर अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कोलकाता के गंगा घाटों पर उमड़ी व्रती व श्रद्धालुओं की भीड़

नीट-2026 के परीक्षार्थियों के लिए लाइव कोर्स साबित होगा गेम-चेंजर

नई दिल्ली/कोलकाता : देश के प्रमुख कोचिंग संस्थान एलन करियर इंस्टीट्यूट की डिजिटल शाखा एलन ऑनलाइन की ओर से मात्र 9990 रुपए की शुरुआती कीमत पर यूनीक लाइव नीट पैकेज की घोषणा की गई है। नीट-2026 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह नीट-पॉवर प्लस कोर्स विशेष रूप से एड-ऑन रिसोर्स के रूप में डिजाइन किया गया है। इस कोर्स में एलन कोटा की अनुभवी व एक्सपर्ट फैकल्टीज की लाइव क्लासेज शामिल हैं। एलन डिजिटल की सीईओ आभा माहेश्वरी ने बताया कि देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए गुणवत्तापूर्ण अतिरिक्त संसाधनों की तलाश में रहते हैं। इस कोर्स की विशेष कीमत यह दर्शाती है कि एलन ऑनलाइन देश के हर स्टूडेंट तक एलन की असाधारण शिक्षा पद्धति और अध्ययन सामग्री पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान ड्रोन से की जाएगी निगरानी

रामनवमी पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राज्य प्रशासन इस बार काफी सतर्क

कोलकाता : बंगाल में रामनवमी पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राज्य प्रशासन इस बार पहले से काफी सतर्क है। पुलिस रामनवमी जुलूसों पर इस बार ड्रोन से भी निगरानी रखेगी। इसके लिए पुलिस थानों को इस निगरानी के लिए ड्रोन का इंतजाम करने को कहा गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ड्रोन से निगरानी मुख्य रूप से विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों पर की जाएगी। इससे पहले, राज्य और कोलकाता पुलिस ने विभिन्न थानों को रामनवमी जुलूसों के घोषित मार्ग और धार्मिक स्थलों के आसपास सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने का भी आदेश

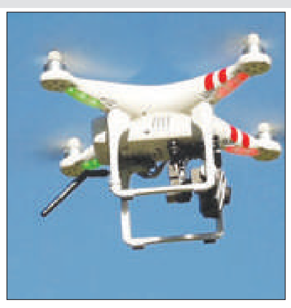

दिया था। अधिकारियों के अनुसार, इस आदेश के बाद कोलकाता व अन्य शहरों के विभिन्न धार्मिक स्थलों और सड़कों पर आपातकालीन आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को जुलूस में ड्यूटी के दौरान बाडी कैमरे का उपयोग करने के लिए भी कहा गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रामनवमी पर इस बार किसी भी नए जुलूस की अनुमति नहीं दी जा रही है। पिछले वर्ष जिन रूट पर जुलूस निकला था, आयोजकों को इस बार भी उसी मार्ग पर जुलूस करने को कहा गया है।

हाल के वर्षों में रामनवमी जुलूस के दौरान राज्य में अशांति की घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन को इस बार भी हिंसा की आशंका है। इसलिए पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है। संबंधित पुलिस थाने जुलूस के आयोजकों के साथ भी नियमित संपर्क में हैं।

रामनवमी के मद्देनजर राज्य पुलिस के कर्मियों की छुट्टियां भी बुधवार से एक सप्ताह के लिए रद कर दी गई हैं। राज्य पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रामनवमी जुलूस के दौरान हथियार प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। कानून के अनुसार तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर भी प्रतिबंधित हैं। पुलिस थानों को पहले से ही यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा गया है कि जुलूस के दौरान कोई आपत्तिजनक या भड़काऊ गाना न बजाया जाए। यदि कोई जुलूस अपना निर्धारित मार्ग बदलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

फर्जी दस्तावेज बनाकर मेडिकल सीट दिलाने का खेल, दो आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता : माणिकतला पुलिस ने मनिकतला थाना केस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रसुन बसु और प्रशांत प्रताप सिंह नाम के दो आरोपियों को मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर धारा 120बी, 420, 406, 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, ये आरोपी अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कई छात्रों को मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाने के नाम पर ठगते थे। इसके लिए ये फर्जी और जाली दस्तावेज तैयार करते थे और लाखों रुपये की धोखाधड़ी करते थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को कोलकाता में माननीय एसीजेएम (खख) कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 11 अप्रैल 2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।

भारतीय मरीजों के लिए कैंसर का इलाज सस्ता बनाया जाना चाहिए : सीआईईयू थिंक टैंक

नई दिल्ली/कोलकाता

नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इकनोमिक अंडरस्टैंडिंग (सीआईईयू) की एक रिपोर्ट ने भारत में बायोसिमिलर को प्रोत्साहित करने के लिए एक सहायक व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो महंगी जैविक चिकित्सा के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प हो सकता है। रिपोर्ट में बायोसिमिलर की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि वे लाखों भारतीयों को प्रभावित करने वाली बीमारियों के लिए अधिक किफायती और लागत प्रभावी उन्नत उपचार में कैसे योगदान दे सकते हैं। सीआईईयू की रिपोर्ट में कहा गया है कि बायोसिमिलर की वहनीयता और उपलब्धता पेटेंट एवरग्रीनिंग से खतरे में है - यह कुछ कंपनियों द्वारा अपनाई गई एक प्रथा है, जिसमें मौजूदा दवाओं में मामूली संशोधन करके बाजार में अपनी विशिष्टता को बढ़ाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी रणनीतियाँ लागत प्रभावी बायोसिमिलर की शुरूआत में देरी करती हैं, जिससे उपचार की लागत अधिक रहती है और भारतीयों के लिए इन तक पहुँच सीमित हो जाती है। जबकि भारत का कानूनी ढांचा इन प्रथाओं पर अंकुश लगाने में सहायक रहा है, रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि बायोसिमिलर के लिए समय पर बाजार में प्रवेश सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

वर्ल्ड हेल्थ डे पर मुट्ठीभर कैलिफोर्निया बादाम के साथ बढ़ाए अपनी सेहत

कोलकाता, समाज्ञा : वर्ल्ड हेल्थ डे, हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन यह याद दिलाया जाता है कि अच्छी सेहत सिर्फ लंबा जीवन नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने का नाम है। पोषण सेहत का एक अहम हिस्सा है और कैलिफोर्निया बादाम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना इसका आसान तरीका हो सकता है।

कैलिफोर्निया बादाम प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन ई जैसे 15 जरूरी पोषक तत्वों का प्राकृतिक स्रोत है, जो समग्र सेहत के लिए फायदेमंद है। 200 से अधिक रिसर्च में यह पाया गया है कि बादाम न केवल ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि दिल की सेहत, ब्लड शुगर कंट्रोल और वजन प्रबंधन में भी मददगार होते हैं।

मैक्स हेल्थकेयर की डाइटीटिक्स रीजनल हेड ऋतिका समद्दार के अनुसार, खराब खानपान और निष्क्रिय जीवनशैली से मोटापा, हृदय रोग और डायबिटीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में समग्र स्वास्थ्य के लिए बादाम, फल और सब्ज़ियां डाइट में शामिल करना जरूरी है।

कोलकाता में 'नेक्सस ऑफ गुड' के कोलकाता चैप्टर का शुभारंभ

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता के **द हेरिटेज स्कूल** में 30 मार्च को 'नेक्सस ऑफ गुड' के कोलकाता चैप्टर का उद्घाटन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नकारात्मकता के स्थान पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है, जिससे समाज के लोगों, विशेषकर युवाओं, पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। यह पहल आईएएस अनिल स्वरूप और पूर्व कोयला सचिव की सोच का परिणाम है। श्री स्वारूप की इस उद्देश्य के प्रति गहरी रुचि के कारण देशभर में 17 चैप्टर स्थापित किए गए हैं, और 18वां चैप्टर कोलकाता में लॉन्च हुआ है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिष्ठित अतिथियों ने भाग लिया, जिनमें कई आईएएस अधिकारी और कोल इंडिया के चेयरमैन भी शामिल थे। कोलकाता चैप्टर के संयोजक हर्ष खेमका हैं। इस अवसर पर तीन प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं, जिनमें भारतीय कैंसर सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी के मित्र और सन्देशखली मां सरोदा महिला एवं ग्रामीण कल्याण सोसाइटी शामिल थे, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों को उपस्थित अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया।

आईकॉनिक व्हाइट व्हिस्की ने 344 दिनों में 50 लाख केस बेचकर सफलता की नई ऊंचाई छुई

कोलकाता, समाज्ञा : एलायड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड (एबीडी), भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्पिरिट्स कंपनी और आईकॉनिक व्हाइट इंटरनेशनल ग्रेन व्हिस्की की निर्माता, ने अपने प्रमुख ब्रांड आईकॉनिक व्हाइट व्हिस्की के 50 लाख (5 मिलियन) केस बेचने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह सफलता वित्तीय वर्ष 24-25 में केवल 344 दिनों में प्राप्त की गई, जिससे यह ब्रांड विश्वभर में तेजी से बढ़ते हुए व्हिस्की ब्रांड के रूप में स्थापित हो गया है। सितंबर 2023 में लॉन्च के बाद से, आईकॉनिक व्हाइट व्हिस्की ने प्रीस्टिज एंड अबव सेगमेंट में अपनी पहचान बनाई है, इसकी आधुनिक पैकेजिंग और मजबूत उपभोक्ता मांग के कारण। पहले वित्तीय वर्ष (2022-23) में 3.2 लाख केस बेचे गए, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा 22.7 लाख केस तक पहुंचा।

एबीडी के प्रबंध निदेशक आलोक गुप्ता ने कहा, आईकॉनिक का 50 लाख केस पार करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह युवाओं में पसंदीदा व्हिस्की बन चुकी है, और हम इसके वैश्विक विस्तार के लिए आशान्वित हैं। ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें गोल्ड मेडल्स और श्रेष्ठ स्वाद पुरस्कार शामिल हैं, जो इसे प्रीमियम व्हिस्की के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं।

अमेजन पे के एक्सक्लूसिव डील्स और रिवॉर्ड्स के साथ प्लान करें अपनी परफेक्ट समर वेकेशन

कोलकाता, समाज्ञा : गर्मियों का मौसम आते ही छुट्टियों की योजना बनाना शुरू हो जाता है। चाहे समुद्र तट पर छुट्टियां बितानी हो, पहाड़ों में शांति चाहिए या किसी रोमांचक शहर में सफर करना हो, अमेजन पे आपको इस समर वेकेशन को किफायती और सुविधाजनक बनाने के लिए शानदार डील्स और रिवॉर्ड्स ऑफर करता है। 7 अप्रैल से अमेजन पे के जरिए फ्लाइट्स, होटलों और मूवी टिकट्स पर आकर्षक छूट का लाभ उठाया जा सकता है। अमेजन पे के साथ फ्लाइट बुकिंग पर 25% तक की छूट और पहली बार फ्लाइट बुक करने पर 12% तक अतिरिक्त छूट मिल रही है। होटलों और होमस्टे पर 18% तक का कैशबैक और मूवी टिकट्स पर 50% तक की छूट भी उपलब्ध है। इसके अलावा, समर फैशन और ट्रैवल शॉपिंग पर 5% तक कैशबैक भी मिलेगा। अमेजन पे के साथ अपनी समर वेकेशन को और भी किफायती और मजेदार बनाएं।

जादवपुर विश्वविद्यालय में अशांति के बाद मेदिनीपुर कॉलेज में बना तनाव, हाई कोर्ट की टिप्पणी

कोलकाता, समाज्ञा

जादवपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में हुए अभूतपूर्व अशांति के कारण मेदिनीपुर कॉलेज भी तनावपूर्ण हो गया था। इस दौरान एसएफआई नेता सुचरिता दास पर हुए अत्याचार के मामले में आईपीएस मुरलीधर शर्मा द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को लेकर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। गुरुवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा कि उन्होंने खुद सीसीटीवी फुटेज देखकर अत्याचार के स्पष्ट प्रमाण पाए हैं। इस मामले में राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त से बातचीत करते हुए न्यायमूर्ति घोष ने पश्चिम मेदिनीपुर महिला थाने के पुनर्गठन की आवश्यकता जताई। उन्होंने राज्य सरकार से कड़ी भाषा में कहा कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो वे सख्त आदेश देने पर मजबूर होंगे। जस्टिस घोष ने कहा, थाना ठीक नहीं है, डीजीपी से कहें कि कार्रवाई करें, अन्यथा मुझे सख्त आदेश देना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, सीसीटीवी फुटेज में अत्याचार के स्पष्ट प्रमाण हैं। किसी को पकड़कर या गिरफ्तार कर अत्याचार करना, आनंदित होना नहीं चल सकता। इसके बाद अदालत ने इस घटना पर और भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, आईजीपी को पूरा फुटेज क्यों नहीं दिया गया? 17 घंटे में से 13 घंटे का फुटेज क्यों दिया गया? 4 घंटे का फुटेज क्यों नहीं दिया गया?

इस मामले में दो छात्राओं पर पुलिस ने अत्याचार किया था। कोलकाता हाई कोर्ट में सुचरिता दास और सुश्रीता सोरेन ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच का जिम्मा आईपीएस मुरलीधर शर्मा को सौंपा था, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने यह टिप्पणी की।

हावड़ा मंडल की 'सृजन' पत्रिका के 37वें अंक का विमोचन एवं मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न

हावड़ा : पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने की। बैठक में सौरिश मुखर्जी, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एवं मंडल कार्यालय के सभी शाखा अधिकारियों की उपस्थिति रही।

बैठक की शुरुआत में मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार द्वारा हावड़ा मंडल की हिंदी ई-पत्रिका 'सृजन' के 37वें अंक का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विमोचन किया गया। इसके उपरांत मंडल के विभिन्न स्टेशनों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को सम्मानित कर पुरस्कृत किया गया।

बैठक का संचालन एवं स्वागत भाषण अभिषेक कुमार, प्रभारी राजभाषा अधिकारी एवं सहायक मंडल सामग्री प्रबंधक/हावड़ा द्वारा किया गया। बैठक में सभी विभागों द्वारा राजभाषा हिंदी में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई तथा इसके अधिकतम प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

इस अवसर पर राजभाषा अनुभाग के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अनुवादकों, जिनमें सालुका लागुरी, आरती कुमारी मिश्रा, बिकाश कुमार साव, सुमित सिंह एवं सुभाष प्रसाद शामिल थे, ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

बैठक के समापन अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना की तथा भविष्य में इसे और अधिक सशक्त बनाने हेतु प्रेरित किया। समापन संदेश के साथ बैठक का विधिवत समापन किया गया।

पूर्व रेलवे के आर.पी.एफ. ने कूड़ा-कचरा फैलाने और धूम्रपान पर नकेल कसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

- **72 हजार से अधिक व्यक्तियों पर की गई कार्रवाई, लगभग 1.1 करोड़ का जुर्माना वसूला**

कोलकाता : स्वच्छता बनाए रखने और यात्रियों के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास में, पूर्व रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) ने कूड़ा-कचरा फेंकने और तंबाकू अधिनियम के तहत कड़े नियम लागू किए हैं। स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, रेलवे अधिकारियों ने स्टेशनों और रेलवे परिसरों में व्यापक अभियान चलाया, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक) के दौरान, रेलवे सुरक्षा बल, पूर्व रेलवे ने रेलवे परिसर में कचरे के अनुचित निपटान के लिए कूड़ा अधिनियम के तहत 44,780 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया और 55.59 लाख का जुर्माना वसूल किया।

इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, आरपीएफ ने तंबाकू अधिनियम के तहत 27,265 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया और रेलवे परिसर के भीतर निषिद्ध क्षेत्रों में धूम्रपान करते पकड़े गए व्यक्तियों पर 54.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इन प्रवर्तन अभियानों के माध्यम से, पूर्व रेलवे का उद्देश्य स्वच्छता बनाए रखना, सार्वजनिक उपद्रव पर अंकुश लगाना और यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ रेलवे वातावरण बनाना है। रेलवे अधिकारी सभी यात्रियों से नियमों का पालन करने और यात्रा को अधिक सुखद एवं स्वास्थ्यप्रद बनाने में सहयोग देने की अपील करते हैं।

जादवपुर में देश विरोधी नारे लिखने के मामले में एक गिरफ्तार

- **पिछले वर्ष आरजी कर कांड के खिलाफ रिक्लेम द नाइट आंदोलन के दौरान लिखे गए थे देश विरोधी नारे**

कोलकाता : महानगर के जादवपुर में 'लड़कियों की रात दखल' कार्यक्रम के दौरान कई लोगों पर देश विरोधी नारे लिखने के आरोप लगे थे। इस बार जादवपुर थाना ने उस घटना में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

पिछले वर्ष अगस्त में आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में एक महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से बंगाल हिल गया था। यह आंदोलन न केवल राज्य के भीतर बल्कि राज्य की सीमाओं को पार कर देश के विभिन्न भागों में भी फैल गया था। महिलाएं विरोध के लिए'रिक्लेम द नाइट' कार्यक्रम आयोजित की थी। न केवल महिलाएं, बल्कि पुरुष भी

इसमें शामिल हुए थे। पीड़िता के लिए 'न्याय' की मांग करते हुए कई लोग सड़कों पर उतर आए थे। हर किसी की आवाज़ में विरोध का स्वर था। कुछ लोग नारे लगा रहे थे, जबकि अन्य बैनर लेकर चुपचाप चल रहे थे। कुछ लोगों के हाथों में मोमबत्तियां थीं। कुछ लोगों ने सड़कों पर विभिन्न विरोध चित्र भी बनाए थे। कुछ लोग सड़कों पर नारे लिखते थे और भित्तिचित्र बनाते हैं। उस समय जादवपुर में सड़क पर राष्ट्र-विरोधी भित्तिचित्र बनाने के साथ-साथ देश विरोधी नारे लिखे गए थे। यह भी लिखा गया था कि हम सशस्त्र क्रांति चाहते हैं।

पिछले साल 14 अगस्त की रात को हजारों लोग आरजी कर घटना के विरोध में सड़कों पर उतरते थे। शहर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक पूरी रात विरोध प्रदर्शन हुआ था। शहर के अलावा राज्य के विभिन्न भागों में भी विरोध प्रदर्शन की लहरें उठीं थी। उसी रात जादवपुर में आठ बी बस स्टैंड के पास कई लोगों ने सड़क पर भित्तिचित्र बनाए। वहां 'हम सशस्त्र क्रांति चाहते हैं' लिखे भित्तिचित्र पर आपत्ति जताई गई। पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने बुधवार को इस घटना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति का नाम चयन सेन है। चयन उन लोगों में शामिल है, जिन पर 'रात दखल' कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लिखने का आरोप हैं।

एनएमडीसी लिमिटेड ने 'आपॉर्च्यूनिटीज फॉर आल' को दी एम्बुलेंस और स्वर्ग रथ

कोलकाता, समाज्ञा : नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएमडीसी लिमिटेड) ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत 'आपॉर्च्यूनिटीज फॉर आल' संस्था को एक वातानुकूलित एम्बुलेंस और स्वर्ग रथ (शव वाहन) प्रदान किया। यह कदम कोलकाता के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो स्वास्थ्य सेवाओं और अंतिम संस्कार से संबंधित जरूरतों को पूरा करेगा। यह संस्था जरूरतमंद और परेशान युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें। एनएमडीसी द्वारा किए गए इस कदम से कोलकाता में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता मिल सकेगी, जो सामुदायिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पूर्व रेलवे के बी.आर. सिंह अस्पताल में उन्नत दर्द प्रबंधन से कैंसर मरीज को मिली राहत

कोलकाता : पूर्व रेलवे के बी.आर. सिंह अस्पताल ने दर्द प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के डॉक्टरों ने एक गंभीर रूप से बीमार कैंसर मरीज को कोलियाक प्लेक्सस ब्लॉक देकर दर्द-मुक्त उपचार का सफल प्रयोग किया है।

महिला सर्जिकल वार्ड-26 में भर्ती इस मरीज को गॉलब्लैडर कैंसर था, जिसका स्थानीय स्तर पर पुनरुत्पत्ति हो चुकी थी और कोलियाक प्लेक्सस प्रभावित था। मरीज को लंबे समय से अत्यधिक पेट दर्द हो रहा था, जो पारंपरिक दर्द निवारक दवाओं से भी नियंत्रित नहीं हो पा रहा था। इस जटिल स्थिति में, अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य निदेशक (एनेस्थीसिया) डॉ. ए.के. रॉय ने कोलियाक प्लेक्सस ब्लॉक की

प्रक्रिया सफलतापूर्वक की, जिससे मरीज को लगातार तीन दिनों तक पूर्ण रूप से दर्द से राहत मिली।

यह चिकित्सा सफलता उन्नत दर्द प्रबंधन तकनीकों का एक उदाहरण है और बीआर सिंह अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग की विशेषज्ञता को दर्शाता है। डॉ. रॉय और उनकी टीम के साथ-साथ वार्ड स्टाफ के समर्पित प्रयासों ने मरीज को राहत दी है, जिससे उनके उपचार में नई आशा और गरिमा बहाल हुई है।

पूर्व रेलवे अपने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है।

रिसड़ा में रामनवमी: सौहार्द्र, एकता और भाईचारे की पेश करेगी मिसाल

❑ **नियमों को मानकर ही निकालनी होगी शोभायात्रा**

हुगली, समाज्ञा : आगामी 6 अप्रैल को देश समेत जिले में भी रामनवमी का पर्व धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा इसको लेकर रिसड़ा उप शहर में उत्सव का माहौल है । रिसड़ा में शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी का पर्व संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घंटे सौहार्द्र और भाईचारा कायम रहे। वर्ष 2023 में राम नवमी की शोभायात्रा के दौरान बिगड़े हालत की वजह से रिसड़ा पर कलंक लगा था। इसलिए इस बार प्रशासन किसी तरह की कोताई बरतने के लिए तैयार नहीं। शोभायात्रा सशर्त निकालनी होगी।

चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक रिसड़ा थाना प्रभारी संजय सरकार की अध्यक्षता में रिसड़ा के रविंद्र भवन में संपन्न हुई। बैठक में डीसीपी श्रीरामपुर अर्नब विश्वास, एसीपी-02 शुभंकर सरकार, जीआरपी अधिकारी, फायर अधिकारी, रिसड़ा नगरपालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा, वाइस चेयरमैन जाहिद हसन खान, श्रीरामपुर नगरपालिका के चेयरमैन गिरधारी साहा, सीआईसी संतोष सिंह, पार्षद शाकिर अली, मनोज सिंह, शशि सिंह झा, मनोज साव, रिसड़ा जामा मस्जिद के इमाम जाकिर हुसैन नूरी, हिन्दू धर्म गुरु और रामनवमी समितियों के आयोजक, श्रीरामपुर थाना प्रभारी सुखमय चक्रबर्ती समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में सभी समुदायों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में शांति, सौहार्द्र और भाईचारे के साथ रामनवमी मनाने की अपील की। एसीपी और डीसीपी ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए शोभायात्रा निकालने की सलाह दी। बीते कल को एक हादसे के तौर पर भुलाकर सौहार्द्र की मिशाल पेश करने की मशवरा दिया गया।

रिसड़ा नगरपालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा ने अपनी कविताओं के माध्यम से शांति और सौहार्द्र बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 'रिसड़ा मिनी भारत है, सौहार्द्र ही इसकी पहचान है।' वहीं, पार्षद शाकिर अली ने कहा कि सनातन धर्म युगों-युगों से चला आ रहा है और हिंदू-मुस्लिम सभी राम के वंशज हैं।

चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर अमित पी. जवालगी ने रामनवमी से पहले डानकुनी, रिसड़ा समेत विभिन्न संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च किया। साथ ही, किसी भी तरह की अफवाह को नजरअंदाज करने की सलाह दी।

श्रीरामपुर नगर पालिका के सीआईसी संतोष सिंह ने कहा कि रिसड़ा की पहचान ऋषि मुनियों के नाम पर होती है किसी भी तरह की अप्रिय घटना शहर के लिए बदनुमा धब्बा बन जाता है इसलिए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन शांति एकता सौहार्द्र भाईचारे के साथ होना चाहिए। डीसीपी अर्णव विश्वास और एसीपी शुभंकर सरकार ने कहा कि शोभायात्रा में डीजे या फिर अस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समय पर तय रूट से ही शोभायात्रा निकालने की अनुमति होगी। किसी भी तरह के विवादित नारों या राजनीतिक नारों से परहेज रखना आवश्यक होगा, ताकि सौहार्द का माहौल न बिगड़े। पुलिस सुरक्षा में हर जगह तैनात रहेगी और सीसीटीवी, वॉच टावर, ड्रोन कैमरों के अलावा खुफिया कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। यह बैठक सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द्र का प्रतीक बनी। रामनवमी के इस पावन पर्व पर रिसड़ा में शांति और आपसी मेल-जोल का वाता-वरण बनाए रखने के लिए सभी वर्गों ने एकजुट होकर पहल की, जिससे यह त्योहार सभी के लिए एक मिसाल बन सके।

बंगाल सरकार को स्कूलों में अमान्य घोषित पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए : माकपा

कोलकाता : माकपा ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य करार दिए जाने के बाद पैदा हुई रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए अन्यथा इससे राज्य की शिक्षा प्रणाली प्रभावित होगी। इससे पहले दिन में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में राज्य सरकार द्वारा संचालित और राज्य से सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था और पूरी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण करार दिया था। पश्चिम बंगाल में माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि राज्य के स्कूलों में शिक्षा प्रणाली प्रभावित होगी क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी चली गई है। सलीम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार को फैसले के बाद रिक्त हुए पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, 'चयन की विश्वसनीयता और वैधता कम हो गई है, इसलिए हमें इसे (उच्च न्यायालय के आदेश को) कुछ संशोधनों के साथ बरकरार रखना होगा।' माकपा नेता ने दावा किया कि ममता बनर्जी सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में अवैधता के कारण राज्य की शिक्षा प्रणाली को भ्रष्ट कर दिया है। सलीम ने दावा किया कि लगभग 26,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां जाने से लगभग एक लाख लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, यह पता लगाया जाना चाहिए कि किसकी गलती से इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां गईं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गहराया शिक्षकों पर संकट

हुगली, समाज्ञा : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिले में शिक्षकों की नौकरी पर संकट आन पड़ा वही जिले में 22 शिक्षकों की नौकरी चली गई। बांसबेड़िया स्थित गैंजेस हाई स्कूल में 41 शिक्षकों में से 15 की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चली गई। जबकि रिसड़ा विद्यापीठ यूनिट -02 में 19 शिक्षक अनुमति प्राप्त है और 7 शिक्षक अननुमोदित है। इनमे से 12 की नौकरी चली गई। गैंजेस हाई स्कूल हिंदी माध्यम स्कूल है, जहां 2200 छात्र पढ़ते हैं। नौकरी गंवाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाएं स्कूल पहुंचे और अदालत के फैसले को सुनकर स्तब्ध हो गए । उनका दावा है कि उन्होंने पूरी पारदर्शिता से नौकरी पाई थी, फिर भी उन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

स्कूल के प्रधानाध्यापक विशाल तिवारी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न सरकारी परियोजनाओं का कार्य भी शिक्षकों से ही करवाया जाता है। हिंदी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पहले से ही कम है, नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने सवाल उठाया कि यदि कुछ लोग अयोग्य थे तो इसके लिए योग्य शिक्षकों की नौकरी क्यों जानी चाहिए?

रिसड़ा विद्यापीठ यूनिट -02 के प्रधानाध्यापक रोशन कुमार मल ने कहा कि शिक्षकों की कमी से पहले ही विद्यालय जुझ रहे थे और छात्रों का पठन पाठन भी ठीक से नहीं हो रहा था। अब जिन शिक्षकों की नौकरी गई है उन पर संकट आन पड़ा है कुछ शिक्षकों की ईएमआई चल रही है वे भुगतान कहां से करेंगे।

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले के अनुसार, लगभग 25,752 नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया है, क्योंकि चयन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताएं पाई गई थीं। न्यायालय ने कहा कि चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हेरफेर और धोखाधड़ी हुई है, जिससे इसकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। हालांकि, जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं, उन्हें अपने वेतन और अन्य भत्तों को वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह तीन महीने के भीतर नई चयन प्रक्रिया पूरी करे। इसके अलावा, विकलांग कर्मचारियों को मानवीय आधार पर छूट दी गई है और उनकी नौकरियां बरकरार रहेंगी।

हावड़ा में जीटी रोड से राम नवमी शोभा यात्रा के लिए पुलिस ने नहीं दी अनुमति

अंजनी पुत्र सेना ने उच्च न्यायालय में की अपील

हावड़ा, समाज्ञा : हावड़ा में आगामी राम नवमी के अवसर पर अंजनी पुत्र सेना द्वारा जीटी रोड से शोभा यात्रा आयोजित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, 2024 में भी इस शोभा यात्रा रैली को पहले अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि पिछले वर्षों, विशेष रूप से 2022 और 2023 में, इसी मार्ग पर आयोजित रैलियों के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा हुई थी। इन घटनाओं के बाद कई एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनकी जांच अब भी जारी है। इस संदर्भ में पुलिस ने शोभा यात्रा के लिए दो वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं।

अंजनी पुत्र सेना के सचिव सुरेंद्र वर्मा

पहला मार्ग अवनी मॉल के पास से फोरशोर रोड होते हुए हावड़ा मैदान तक और दूसरा मार्ग राज-ारामतला से नेताजी सुभाष रोड होते हुए कदमतला, पावर हाउस और फांसी तल्ला मोड़ से होते हुए हावड़ा मैदान तक है।

अंजनी पुत्र सेना के सचिव सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि उनका उद्देश्य पुराने मार्ग से ही शोभा यात्रा निकालना है। इसके लिए उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से जल्द ही अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शोभा यात्रा शांतिपूर्वक और सभी नियमों और शर्तों का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। उनका मानना है कि यह यात्रा सिर्फ धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक नहीं होगी, बल्कि यह समाज में एकता, भाईचारे और आपसी समझ का भी संदेश देगी।

गंगासागर में बासंती पूजा की धूम, थीम आधारित पंडाल बना आकर्षण का केंद्र

कोलकाता : गंगासागर में इस वर्ष बासंती पूजा थीम की छवि लिए अन-ोखे अंदाज में मनाई जा रही है। गुरुवार से बासंती पूजा 2025 की शुरुआत पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में हो चुकी है। वहीं, दक्षिण 24 परगना जिले के गंगासागर स्थित काली बाजार में इस पूजा का 57वां वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के साथ मिलन मेला का आयोजन भी किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हो रहे हैं।

गुरुवार को महाषष्ठी के दिन शाम में इस पूजा का शुभ उद्घाटन किया सुंदरबन विकास मंत्री एवं सागर के विधायक बंकिमचंद्र हाजरा ने। उनके साथ सागर के बीडीओ कनैया कुमार राव, पंचायत समिति की अध्यक्ष सबीना बीबी, उपाध्यक्ष स्वपन कुमार प्रधान, जिला परिषद सदस्य संदीप कुमार पात्र और गंगासागर ग्राम पंचायत के उपप्रधान हरिपद मंडल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस वर्ष पूजा पंडाल की थीम बांस की दरमा (चटाई) से तैयार की गई है, जो दर्शकों को आकर्षित कर रही है। पंडाल को विशेष रोशनी और भव्य सजावट से सजाया गया है। पंडाल के पास ही बाल विवाह, बिजली चोरी, 'सेफ ड्राइव, सेव लाइफ' जैसे सामाजिक संदेशों को दिखाते हुए कई झांकी भी प्रस्तुत की गई हैं, जो लोगों को जागरूक कर रही हैं।

पूजा के दौरान सांध्यकालीन कार्यक्रमों में विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं, जो इस आयोजन को और भी खास बना रही हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस अनूठी बसंती पूजा का आनंद लेने के लिए उमड़ रहे हैं।

कोलकाता घूमाने के बहाने मां ने सौतेली बेटी को बीच सड़क पर छोड़ा

यौनकर्मियों ने बच्ची को बचाया

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता घूमने के बहाने एक महिला ने अपनी सौतेली बेटी को सड़क किनारे छोड़ दिया। 13 वर्षीय नाबालिग घूमते-घूमते सोनागाछी पहुंच गयी। जहां यौनकर्मियों के बच्चों द्वारा गठित संगठन 'आमरा पदातिक' द्वारा उस बच्ची को बचा लिया गया। बुधवार की सुबह 'आमरा पदातिक' की सदस्य कोहिनूर बेगम ने जोड़ाबागान इलाके में एक नाबालिग बच्ची को बैठे देखा। संदेह होने वह बच्ची से पूछताछ करने लगी। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि उसकी सौतेली मां उसे घुमाने के बहाने सुबह कोलकाता ले आई थी। पार्क सर्कस इलाके में उसकी मां दो मिनट में

वापस आने का कहकर चली गई और वापस नहीं आयी। घर लौटने की कोशिश में बच्ची जोड़ाबागन के यौनपल्ली इलाके में पहुंच गयी। इसके बाद 'आमरा पदातिक' ने पूरे मामले की सूचना बाल संरक्षण आयोग और जोड़ाबागान पुलिस स्टेशन को दी। पुलिस ने इस मामले की थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। बाल संरक्षण आयोग इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हुए जांच करेगा।

चैत्री छठ पर हुगली के गंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब

हुगली, समाज्ञा : चैत्र महीने में मनाए जाने वाले चार दिवसीय छठ पर्व के पहले अर्घ्य के अवसर पर हुगली जिले के रिसड़ा, श्रीरामपुर, चांपदानी, बांसबेड़िया समेत अन्य गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। रिसड़ा में नगरपालिका चेयरमैन विजय सागर मिश्रा और चांपदानी में चेयरमैन सुरेश मिश्रा ने गंगा घाटों का जायजा लिया। छठ व्रतियों ने अपने पुत्रों की दीर्घायु, परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना के साथ गंगा में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। महिलाओं और पुरुषों ने पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से इस पवित्र अनुष्ठान को संपन्न किया। छठ पर्व के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए चंदननगर पुलिस

कमिश्नरेट की ओर से घाटों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पुलिस कर्मियों के अलावा रिसड़ा चांपदानी नगरपालिका की तरफ से स्वयंसेवकों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया। अर्घ्य के समय घाटों पर दीपों की जगमगाहट, छठ गीतों की गूंज और भक्तिभाव से भरे श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। श्रद्धालु पारंपरिक परिधानों में सजे नजर आए और व्रतियों ने कठिन उपवास रखते हुए पूरी आस्था से पूजा-अर्चना की। छठ महापर्व का दूसरा अर्घ्य उगते हुए सूर्य को दिया जाएगा, जिसके साथ ही यह पावन पर्व संपन्न होगा।

राम नवमी से पहले आग्नेयास्त्र संग बदमाश गिरफ्तार

हुगली : रामनवमी से पहले चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर अमित पी जवालगी संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों का पुलिस के आला अधिकारियों और पुलिस बल के साथ रूट मार्च कर रहे है। ताकि राम नवमी का पर्व शांति सौहार्द्र से सम्पन्न करवाया जा सके। पुलिस लगातार अराजक तत्वों और गड़बड़ी फैलाने वालों पर नजर गड़ाए हुए है। इसी क्रम में जिले कुख्यात गैंस्टर रमेश महतो के गिरोह का सदस्य गौरीशंकर बारी को हथियार के साथ रिसड़ा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामनवमी से पहले पुलिस प्रशासन विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही है। गुरुवार को पुलिस ने रिसड़ा के मोड़पुकुर झिलपाड़ा इलाके में छापामारी कर एक पाइप गन और एक राउंड कारतूस के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी को शुक्रवार को श्रीरामपुर कोर्ट में पेश करेगी।

श्री श्री सिद्धि विनायक भक्त मंडल का दो दिवसीय सेवा शिविर हुआ संपन्न

कोलकाता, समाज्ञा : श्री श्री सिद्धि विनायक भक्त मंडल द्वारा आयोजित दो दिवसीय सेवा शिविर, इस वर्ष भी शानदार ढंग से संपन्न हुआ। हर साल की तरह इस बार भी मां गवरजा की शोभा यात्रा के दौरान कोठारी पार्क, नींबूतला में शीतल जल और केसरिया शर्बत की व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा में शामिल हुए। बड़ाबाजार क्षेत्र दो दिनों के लिए मिनी राजस्थान का रूप धारण कर चुका था, जहां 9 गवरजा मंडलियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर गायन प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन का भक्तों ने भरपूर आनंद लिया और शोभा यात्रा में मां गवरजा विभिन्न प्रकार के रथों पर विराजमान रहीं। इस धार्मिक सेवा कार्य को सफल बनाने में संरक्षक अशोक द्वारकानी, संस्थापक जनार्दन अग्रवाल, चेयरमैन सुशील कोठारी, सभापति अमरनाथ सिंह, महेंद्र पुरोहित, अभिषेक तापड़िया और मधुसूदन सफर का योगदान उल्लेखनीय था। इस कार्यक्रम की जानकारी सह सचिव राजेंद्र कोठारी ने दी।

सरकार को जमीन दान देने के बावजूद नहीं मिली नौकरी, हाई कोर्ट जाएगा पीड़ित परिवार

पीड़ित का आरोप-उसके स्थान पर ग्राम पंचायत प्रधान के पति को मिली हैं नौकरी

कोलकाता : बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में सरकार को जमीन दान देने के बावजूद एक पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं मिली है। इस मामले में पीड़ित परिवार अब हाई कोर्ट का रूख करेगा। इस घटना में संदेशखाली ब्लाक क्रमांक एक के कालीनगर ग्राम पंचायत की कार्यवाहक प्रधान सुनीता बोर और उसके पति भोल-ानाथ बोर आरोपित हैं।

लगभग पांच साल पहले संदेश-खाली ब्लाक नंबर एक के अंतर्गत कालीनगर ग्राम पंचायत के घटिहारा इलाके में एक जलाशय टैंक बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी। वादा यह था कि एक बीघा जमीन दान करने पर दो व्यक्तियों को नौकरी मिलेगी। इलाके के निवासी भास्कर चंद्र पंडा ने लोक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग को एक बीघा से अधिक जमीन दान में दी थी। इसके मुताबिक भास्कर चंद्र पांडा के बेटे और उनके भतीजे बिप्लब पांडा को जमीन में साझेदार के रूप में नौकरी देने का वादा किया गया था। लेकिन आरोप यह है कि बिप्लब को अब तक उस नौकरी से वंचित रखा गया है। उनकी मांग है कि या तो उन्हें नौकरी दी जाए या फिर उनकी जमीन का हिस्सा वापस किया जाए। उन्होंने स्थानीय पंचायत प्रधान कार्यालय, लोक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग, उप-मंडल प्रशासक और यहां तक कि जिला मजिस्ट्रेट को भी पत्र लिखा है। लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं बिप्लब का दावा है कि लोक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग को जमीन दान करने के बावजूद उसकी जगह पर पंचायत प्रमुख सुनीता बोर का पति भोलानाथ बोर काम कर रहा है। इसलिए, यदि उन्हें तत्काल नौकरी नहीं मिली तो वे अपनी जमीन का हिस्सा वापस करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। इस बीच जमीन पर पानी की टंकी बना दी गई।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भारत सरकार के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से पेंशन वितरण की मंजूरी

मुंबई/कोलकाता : आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भारत सरकार के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) द्वारा अपनी ओर से पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया गया है। अब बैंक केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन दे सकेगा, जिसमें अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, पूर्व सांसद, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सिविल मंत्रालयों व विभागों (रेलवे, डाक, टेलीकॉम और रक्षा को छोड़कर) के अधिकारी शामिल हैं। पेंशनभोगी अब अपनी पेंशन सीधे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट में प्राप्त कर सकेंगे। सीपीएओ (भारत सरकार) और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बीच तकनीकी रूप से एकीकरण पूरा हो चुका है और अब बैंक पेंशन वितरण के लिए पूरी तरह तैयार है।

2025 की पहली तिमाही में आवासीय बिक्री 3,858 यूनिट तक पहुंची: नाइट फ्रैंक इंडिया

कोलकाता : नाइट फ्रैंक इंडिया ने अपनी नई रिपोर्ट - इंडिया रियल एस्टेट: रेजीडेंशियल एंड ऑफिस जनवरी-मार्च 2025 (2025 की पहली तिमाही) में बताया है कि साल 2025 की पहली तिमाही में, कुल 0.16 मिलियन वर्ग फीट ऑफिस स्पेस लीज पर दिया गया है जो साल 2024 की पहली तिमाही की तुलना में 16% की गिरावट को दर्शाता है। साल 2024 की पहली तिमाही में 0.20 मिलियन वर्ग फीट ऑफिस स्पेस लीज पर दिया गया था। इस गिरावट के बावजूद, शहर के औसत ऑफिस किराए में 9% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि हैदराबाद के साथ-साथ शीर्ष आठ शहरों में सबसे ज्यादा 42 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रति माह तक पहुंच गया है। नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर डायरेक्टर-ऑक्यूपायर स्ट्रैटेजी एंड सॉल्यूशंस, जॉयदीप पॉल ने कहा, कोलकाता के बाज़ारों में भारतीय कंपनियों के बढ़ने से आने वाले समय में यहाँ व्यापार के बहुत मौके मिलेंगे।

वक्फ विधेयक असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ : तृणमूल

नयी दिल्ली/कोलकाता : राज्यसभा में बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस ने वक्फ़ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि यह विधेयक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के साथ ही राज्यों के अधिकारों को भी प्रभावित करता है।

उच्च सदन में वक्फ़ संशोधन विधेयक, 2025 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सदस्य मोहम्मद नदीमुल हक ने कहा कि यह विधेयक सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बल्कि पूरे देश से जुड़ा है और यह मौलिक अधिकारों का हनन भी करता है।उन्होंने इस विधेयक को गैर-जरूरी कदम बताया और कहा कि यह असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है।

हक ने कहा कि संविधान कोई किताब नहीं बल्कि देश को रास्ता दिखाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संघवाद की भावना के खिलाफ भी है और इसमें सुधारों के नाम पर परंपराओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए राज्यों के अधिकारी छीने जा रहे हैं।

तृणमूल सदस्य ने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से स्पष्ट है कि वक्फ मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा और सरकारी अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं।

उन्होंने इसे भेदभावकारी बताते हुए कहा कि कम से कम पांच साल तक मुस्लिम धर्म का अनुसरण करने वाले ही वक्फ के कामकाज से जुड़ सकेंगे। उन्होंने सवाल किया कि यह कौन तय करेगा कि अमुक व्यक्ति पांच साल से मुस्लिम धर्म का भलीभांति अनुसरण कर रहा है या नहीं।हक ने कहा कि इस विधेयक में संपत्ति के दस्तावेजों पर भी जोर दिया गया है लेकिन कई संपत्ति पीढ़ियों से हैं और मौखिक आधार पर दिए गए थे, वैसे मामलों में दस्तावेज कैसे उपलब्ध होंगे। उन्होंने विधेयक को सांस्कृतिक विद्वेष फैलाने वाला भी बताया और इस बात पर आपत्ति जतायी कि वक्फ बोर्ड और परिषद में गैर-मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं।उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक के प्रावधानों से अदालतों पर भी बोझ बढ़ेगा जहां पहले ही बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं।

बेलगछिया में नालियों की जाम समस्या पर लोगों का विरोध, पुलिस से हुई तीखी झड़प

हावड़ा, समाज्ञा : हावड़ा के बेलगछिया इलाके में गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों ने नालियों की जाम और गंदे पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन लगभग दो घंटे तक चला। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। वे यह भी कह रहे थे कि नेताओं और मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन केवल कागजी बातें बनकर रह गए हैं, और इन समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बार-बार आश्वासन मि3लने के बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोग गंदे और सड़े पानी में रहने को मजबूर हैं, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसे खतरनाक रोगों का खतरा बढ़ गया है। इस स्थिति से तंग आकर उन्होंने विरोध स्वरूप सड़क पर उतरने का निर्णय लिया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि नालियों और जल निकासी के लिए बनाए गए खालों की सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण जल निकासी की समस्या बनी हुई है। गंदे पानी से जूझ रहे लोग अब इस समस्या के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ प्रदर्शनकारियों की तीखी झड़प भी देखने को मिली।

कोलकाता साइबर पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड घोटाले में दो लोगों को किया गिरफ्तार

कोलकाता : कोलकाता साइबर पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड जारी करने और साइबर अपराधियों को बेचने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी साइबर पीएस, कोलकाता केस नंबर 13/25 दिनांक 04.03.2025 के तहत की गई है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66उ, 66ऊ, 43 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने 2 अप्रैल 2025 की देर शाम उत्तर 24 परगना जिले के गैघाटा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आरोपी कमलेश मलाकार (26 वर्ष) को गिरफ्तार किया। वह उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर के शिमलपुर का निवासी है। पुलिस के अनुसार, कमलेश मलाकार कमलेश टेलीकॉम नाम से एक पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) चला रहा था, जिसके जरिए वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड जारी करता था और उन्हें साइबर अपराधियों को बेचता था। इस दौरान पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी जब्त कीं। गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया कानूनी नियमों और मानक संचालन प्रक्रिया (एसअ-ोपी) के तहत पूरी की गई, और आरोपी के परिजनों को गिरफ्तारी की जानकारी लिखित रूप में दी गई।

इसके बाद आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 3 अप्रैल 2025 को तड़के अशोकनगर थाना क्षेत्र में एक और छापेमारी की, जिसमें समरेश सरकार (25 वर्ष) नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। समरेश सरकार, जो अशोक नगर, कल्याणगढ़ का निवासी है, फर्जी तरीके से प्राप्त सिम कार्ड का इस्तेमाल कर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की हेल्पलाइन पर कॉल करके लोगों को धोखा देता था। धोखाधड़ी के बाद वह इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड को नष्ट कर देता था और नए अवैध रूप से प्राप्त सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था।

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी साइबर अपराधियों के नेटवर्क का हिस्सा थे और इनके माध्यम से बड़ी संख्या में फर्जी सिम कार्ड साइबर ठगों तक पहुंचाए जाते थे। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है।

न्यूज इन ब्रीफ

शिव मंदिर परिसर में हमला कर पांच लोगों को घायल किया

भदोही (उप्र) : उत्तर प्रदेश के भदोही में एक शिव मंदिर के निर्माण स्थल पर एक दर्जन से अधिक हथियारबंद हमलावरों ने कथित तौर पर हमला किया, जिसमें कर्नाटक के एक व्यक्ति और मंदिर की महंत माता राज लक्ष्मी मंदा के सहयोगियों सहित पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। ज्ञानपुर थाना के प्रभारी निरीक्षक विष्णु प्रभा सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह घटना सुंदरवन कटेबना में 31 मार्च को घटी और मंदिर परिसर में हंगामे की सूचना पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर भाग निकले। पुलिस ने हमले में घायल पांच लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया।

गन्ने के उबलते रस में गिरने से मजदूर की मौत

मुजफ्फरनगर (उप्र) : जिले के पुरकाजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिनगर गांव में बृहस्पतिवार को गुड़ बनाने वाली एक फैक्टरी में एक व्यक्ति की गन्ने के उबलते रस में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। थाना प्रभारी (एसएए-चओ) जयवीर सिंह ने बताया, गुड़ बनाते समय मजदूर शोकेंद्र (30) की गन्ने के उबलते रस में गिरने से मौत हो गई। सिंह ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना की जांच की जा रही है। इस बीच, पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया है कि शोकेंद्र को जानबूझकर उबलते रस में फेंका गया था।

झारखंड के पलामू में एक लाख रुपये का इनामी नक्सली गिरफ्तार

मेदिनीनगर : झारखंड के पलामू जिले से एक लाख रुपये के इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि भाकपा (माओवादी) से अलग हुए संगठन तृतीया सम्मेलन प्रस्तुति समिति (टीएसपीसी) के सदस्य सुभाष यादव उर्फ जिबलाल यादव को बुधवार रात नावा बाजार थाना क्षेत्र के तुरीगदार पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर भूमि अतिक्रमण करने का आरोप लगाया

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर बृहस्पतिवार को सीधा हमला करते हुए इस पर भूमि अतिक्रमण करने का आरोप लगाया और इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इसका मनमाना दावा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां श्रृंगवेरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'आप यहां निषादराज की पौराणिक भूमि पर कब्जा देख रहे हैं ना। शहर में जगह-जगह वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। यहां तक की कुंभ के समय भी बयान दिए गए कि कुंभ की भूमि भी वक्फ की है। हमने पूछा था- क्या वक्फ बोर्ड भू-माफिया बन गया है।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार के तहत इस तरह के अतिक्रमण हटा दिए गए हैं

और माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर खदेड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, 'निषाद राज से जुड़ी पवित्र भूमि समेत कई जगहों पर वक्फ के नाम पर अतिक्रमण किया गया। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों के बावजूद भव्य और दिव्य कुंभ मेले का आयोजन किया गया।' मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड की कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधायी कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी सराहना की। उन्होंने कहा, 'हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई है। इस मुद्दे को हल करने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है और अब इसे राज्यसभा में भी पारित किया जाएगा।'

जिनके मन में राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं, वे महाकुंभ जैसा आयोजन नहीं कर सकते: योगी आदित्यनाथ

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि जिनके मन में राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं है, वे महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि महाकुंभ 2025 ने देश-प्रदेश को बहुत कुछ दिया और इतना बड़ा आयोजन राम भक्त ही कर सकते हैं। यहां श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान श्रीराम के प्रिय सखा निषादराज गुह्य के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान राम और निषादराज के बीच मित्रता का यह अद्भुत संगम आज फिर देखने को मिल रहा है। वही मित्रता भाजपा और निषाद पार्टी की है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयागराज अब सामान्य रूप से इलाहाबाद नहीं रहा। अब यह प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छिपाते थे, वे नहीं चाहते थे कि इस पौराणिक नगर को नयी पहचान मिले क्योंकि उनके लिए उनका 'वोटबैंक' महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, 'महाकुंभ 2025 ने देश-प्रदेश को बहुत कुछ दिया और इतना बड़ा आयोजन राम भक्त ही कर सकते हैं। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं है, वे महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन नहीं कर सकते।'

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अमित शाह की टिप्पणी पर लालू प्रसाद ने किया पलटवार

पटना : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस तंज के एक दिन बाद कि वक्फ (संशोधन) विधेयक ने 'राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की इच्छाओं को पूरा किया है', बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को पलटवार किया। शाह ने प्रसाद के 2013 के भाषण का हवाला देते हुए लोकसभा में यह टिप्पणी की थी। वर्ष 2013 में प्रसाद सदन के सदस्य थे और उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ में 'अधिक कड़े' संशोधनों का आह्वान किया था। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) तत्कालीन संप्रग सरकार का हिस्सा

था। प्रसाद ने अपने 'एक्स' हैंडल पर भाषण का एक छोटा वीडियो क्लिप साझा करते हुए 'भाजपा और संघ के अज्ञानी मूर्खों' की आलोचना की, लेकिन शाह या किसी अन्य नेता का नाम लेने से परहेज किया। राजद प्रमुख ने लिखा, 'मैंने वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए एक कठोर कानून की वकालत की थी, जिसे आप हड़पने की कोशिश कर रहे हैं।' प्रसाद पिछले सप्ताह वक्फ (संशोधन) विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित धरने में शामिल हुए थे। राजद प्रमुख ने कहा, 'मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं ऐसे समय में संसद में नहीं हूं जब मुसलमानों, अन्य अल्पसंख्यकों और आम तौर पर गरीबों के अधिकारों और संविधान पर हमला हो रहा है।

उच्च न्यायालय से सपा नेता आजम खान को राहत, गिरफ्तारी पर रोक लगी

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर जिले के गंज थाना में 2007 में दर्ज एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने इस मामले में आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, अफसर खान नाम के एक व्यक्ति ने 2007 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि आजम खान के इशारे पर उसका घर ध्वस्त करा दिया गया था तथा पुलिस ने जांच के बाद 2007 में ही अंतिम रिपोर्ट दायर कर दी थी जो संबंधित अदालत के समक्ष लंबित है।

आरेडिका ने वित्तवर्ष 2024-25 में सर्वाधिक कोच उत्पादन का बनाया रिकॉर्ड

रायबरेली : आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2025 कोचों का उत्पादन कर अभी तक का सर्वाधिक कोच उत्प-ादन का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। कोविड-19 के बाद आरेडिका पिछले 2 वर्षों से लगातार कोच उत्पादन के नये आयाम स्थापित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एमसीएफ ने 1684 कोच बनाएं थे, यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले 16% अधिक था। इसी कडी को आगे बढाते हुए आरेडिका ने वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 2025 कोच का उत्पादन कर पिछले वर्ष से 20% ज्यादा कोच बनाये। इन 2025 कोचों में विभिन्न प्रकार के कोच हैं जिसमें दीनदयालु के 582 कोच, स्लीपर के 500 कोच, 3टीयर इकोनोमिक के 300 कोच, वातानुकूलित 3टीयर के 276 कोच, जनरल चेयर कार 112, पावर कार 80कोच, 2टीयर के 60 कोच, दिव्यांगजनो के लिए 46 कोच, मेमू के 20 कोच, तेजस के 21 कोच, पार्सलवैन 14, एसी चेयरकार तथा अन्य 14 कोचों का निर्माण किया गया है। भारतीय रेल द्वारा रेल यात्रा में आर्थिक रूप से सामान्य व मध्यम वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए जनरल सीटिंग और स्लीपर श्रेणी के कोचों की संख्या लगातार बढाई जा रही है इसीलिए आरेडिका ने इस वर्ष बनने वाले 2025 कोचों में 1274 कोच सामान्य जनरल एवं स्लीपर के बनाये जिससे सामान्य व गरीब वर्ग सुविधाजनक एवं आरामदायक यात्रा कर सकें जो कुल उत्पादन का 63% हैं निर्मित कोचों में 751 एसी कोच तथा 1274 नॉन एसी कोच है जो निर्माण कार्य की दक्षता और गुणवत्ता को दर्शाता है। निर्माण कार्य के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता को बनाए रखने में आरेडिका के विभिन्न विभागों का सामंजस्य रहा है।आरेडिका के महाप्रबंधक प्रशान्त कुमार मिश्रा ने बताया कि रिकॉर्ड उत्पादन का यह लक्ष्य आरेडिका के सभी प्रधान मुख्य विभागाध्यक्षों के नेतृत्व में टीम एमसीएफ के कोच उत्पादन के प्रति समर्पण की भावना से संभव हुआ है तथा आने वाले वर्ष में आरेडिका में मेमू, वन्देभारत ट्रेन सेट्स का उत्पादन किया जायेगा। इस अवसर पर मिश्रा ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और यूनियनों के प्रतिनिधियों, एवं संविदा कर्मचारियों को बधाई दी।

न्यूज अपडेट

वक्फ बोर्ड कुछ लोगों की 'जागीर' बन गया था- केशव मौर्य

कौशांबी (उप्र) : राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को कहा कि वक्फ बोर्ड कुछ लोगों की 'जागीर' बन गया था। अपने गृह जनपद कौशांबी में नवरात्रि के अवसर पर शीतला माता का दर्शन पूजन करने के बाद मां शीतला अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत में मौर्य ने कहा कि वर्तमान में वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है तथा नए कानून के तहत जमीन को जांच के बाद ही वक्फ की संपत्ति माना जाएगा और वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच जिला कलेक्टर की निगरानी में होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा इस कानून (वक्फ संशोधन विधेयक) का विरोध मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता चाहने वाले लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और यह कानून 90 प्रतिशत गरीब मुसलमानों के हित में है। मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370, राम मंदिर और तीन तलाक रोधी कानून का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद को 370 हटाया, राम मंदिर का निर्माण करवाया और मुस्लिम महिलाओं के हित में तीन तलाक कानून बनाया।

जद(यू) नेता ने वक्फ विधेयक पर पार्टी के रुख को लेकर इस्तीफा दिया

पटना : जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के पार्टी के रुख की बृहस्पतिवार को आलोचना की। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया। जद (यू) अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में अंसारी ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के रुख ने उन लाखों भारतीय मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया है, जो मानते थे कि जद(यू) धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखेगी। पत्र में अंसारी ने कहा, 'हमारे जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों को धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के एक सच्चे ध्वजवाहक के रूप में आप (नीतीश) पर अटूट विश्वास था। हालांकि, अब यह विश्वास टूट गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जद (यू) द्वारा अपनाए गए रुख से लाखों समर्पित भारतीय मुसलमानों और कार्यकर्ताओं को गहरा सदमा लगा है।' उन्होंने कहा, 'हम ललन सिंह द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण और इस विधेयक के समर्थन को लेकर बेहद निराश हैं।'

राहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई टली

सुलतानपुर (उप्र) : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को वादी की तरफ से गवाह पेश नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 अप्रैल तय की है। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से संबंधित मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन वादी की तरफ से गवाह के पेश न होने पर आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 अप्रैल नियत की है। पिछली सुनवाई 20 मार्च को थी।

पांच दिन में 100 करोड़ तक भी नहीं पहुंची 'सिकंदर'

सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' 30 मार्च 2025 को ईद के मौके पर रिलीज हुई थी। पहले दिन इसने भारत में महज 26 करोड़ रुपये कमाए। यह आंकड़ा सलमान के पिछले ईद रिलीज जैसे 'भारत' (42.30 करोड़) और 'टाइगर जिंदा है' (33 करोड़) से काफी कम था। इस फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। वहीं, सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने आलोचना की है। इन वजहों से फिल्म के कलेक्शन पर गहरा असर देखने को मिला है।

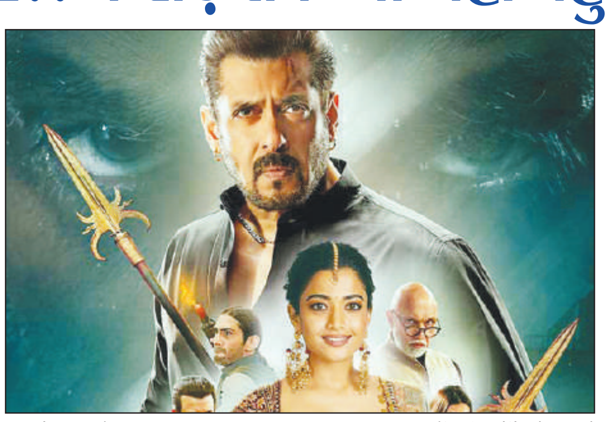

हालिया रिलीज फिल्मों से है काफी पीछे

हालिया बड़ी फिल्मों से तुलना करें तो 'सिकंदर' इन फिल्मों से काफी पीछे है। 'पुष्पा 2' ने पहले दिन दो दिन में हिंदी में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। वहीं, 'छावा' ने तीन दिन में 100 करोड़ी क्लब में अपनी जगह बना ली थी। 'सिकंदर' का प्रदर्शन इनके मुकाबले अब तक काफी कमजोर रहा है।

स्क्रिप्ट, निर्देशन और अदाकारी ने डुबोई लुटिया

फिल्म की स्टारकास्ट में सलमान खान लीड रोल में हैं। रश्मिका मंदाना उनकी हीरोइन हैं जो 'पुष्पा 2' और 'एनिमल' की सफल फिल्मों में दिख चुकी हैं। उनके अलावा फिल्म में काजल अग्रवाल, शरमन जोशी, और सत्यराज जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म के निर्देशक ए आर मुरुगदास हैं, जिन्होंने 'गजनी' जैसी हिट फिल्म दी थी। साजिद नाडियाडवाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। कई बड़े सितारों के बावजूद स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की कमजोरी ने फिल्म को काफी ज्यादा प्रभावित किया है।

'रेस 3' से भी पीछे चल रही 'सिकंदर'

सलमान की यह फिल्म पांच दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी है। फिल्म का हाल 'रेस 3' से भी बुरा है। उस फिल्म ने तीन दिन में 106.14 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन सिकंदर अब तक ऐसा नहीं कर सकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने गुरुवार को चार करोड़ सात लाख रुपये की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 88.32 करोड़ रुपये हो गया है।

फिल्म पर मंडरा रहा फ्लॉप होने का खतरा

कुल मिलाकर 'सिकंदर' सलमान के स्टारडम के बावजूद औसत प्रदर्शन कर रही है। ईद के बाद इसकी कमाई में बड़ी गिरावट दिख रही है। इससे फिल्म पर फ्लॉप होने का खतर मंडराने लगा है। 'टाइगर 3' और 'बजरंगी भाईजान' से अगर इसकी तुलना करें तो यह फिल्म दोनों के सामने कहीं भी नहीं टिकती है। 'सिकंदर' को सलमान की टॉप फिल्मों में जगह बनाने के लिए मजबूत वीकएंड और बेहतर वर्ड ऑफ माउथ की जरूरत थी जो इसे नहीं मिल सका है।

'सोलमेट' को लेकर फरदीन खान का लेटेस्ट पोस्ट कर देगा हैरान

बॉलीवुड अभिनेता फरदीन खान ने वैसे तो काफी समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन फिर उन्होंने निर्देशक संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज 'हीरामंडी' से वापसी की और अपने अभिनय से एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया। वहीं आज (3) अप्रैल को फरदीन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सोलमेट को लेकर एक पोस्ट जारी किया है, जिस पर मनीषा कोइराला ने अपनी राय शेयर की है।

फरदीन खान का इंस्टाग्राम पोस्ट

फरदीन खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें कई रंगों के बीच दो हाथ नजर आ रहे हैं। एक नीले रंग का और एक लाला रंग का। इस पोस्ट के साथ फरदीन ने कैप्शन में लिखा, ''लोग सोचते हैं कि एक सोलमेट आपके लिए एक दम सही है, और ऐसा ही हर कोई चाहता है, लेकिन एक सच्चा सोलमेट एक आईना है, वह व्यक्ति जो आपको वह सब कुछ दिखाता है, जो आपको पीछे खींच रहा है, वह व्यक्ति जो आपको आपके ध्यान में लाता है ताकि आप अपना जीवन बदल सकें।''

सोलमेट - सभी दीवारें तोड़ देते हैं

आगे फरदीन ने लिखा, ''एक सच्चा सोलमेट शायद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिससे आप कभी मिलेंगे, क्योंकि वे आपकी दीवारें तोड़ देते हैं और आपको जगा देते हैं। वे आपके जीवन में आपकी सभी परतों को दिखाने करने के लिए आते हैं। एक सोलमेट का उद्देश्य आपको झकझोरना है, आपके अहंकार को तोड़ना है। आपको आपकी बाधाओं को दिखाना है, आपके दिल को खोलना है ताकि नई रोशनी अंदर आ सके और आपको इतना हताश और नियंत्रण से बाहर कर दें कि आपको अपना जीवन बदलना पड़े।''

फरदीन के इस पोस्ट पर मनीषा कोइराला ने दिया रिएक्शन

फरदीन खीन और मनीषा कोइराला एक साथ वेब सीरीज 'हीरामंडी' में नजर आए थे। इस सीरीज में मनीषा ने मल्लिकाजान की भूमिका निभाई थी। वहीं फरदीन ने एक नवाब वली मोहम्मद का किरदार निभाया है। इस सीरीज को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। वहीं आज मनीषा ने फरदीन के इस पोस्टर को लेकर लिखा, 'कितना सही...।'

दिशा पाटनी को लेकर 'फौजी' के निर्माताओं ने दिया बड़ा अपडेट

हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि अभिनेत्री दिशा पाटनी को प्रभास की आने वाली पीरियड ड्रामा फिल्म 'फौजी' में दूसरी अहम भूमिका के लिए चुना गया है, लेकिन फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए कास्टिंग हो चुकी है, और दूसरी मुख्य भूमिका वाली अभिनेत्री होने की खबर झूठी है।

दिशा से नहीं किया गया संपर्क

प्रोडक्शन टीम ने इसे खारिज कर दिया है। टीम ने साफ किया है कि उन्होंने इस भूमिका के लिए अभिनेत्री से कभी संपर्क नहीं किया।

फौजी में नहीं होंगी दिशा

मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक प्रोडक्शन हेड ने स्पष्ट किया है यह सब अफवाह है, और हमने दिशा पाटनी से संपर्क नहीं किया है।

दिशा ने अभी तक इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले, यह बताया गया था कि दिशा फौजी में दूसरी मुख्य भूमिका निभाएंगी। यह भी कहा गया था कि दिशा से एक्शन से भरपूर फिल्म के 'ग्लैमर' को बढ़ाने के लिए संपर्क किया गया था।

फिल्म में होंगे ये किरदार

आपको बता दें कि फिल्म 'फौजी' का निर्देशन हनु राघवपुडी ने किया है। 'फौजी' एक बहुप्रतीक्षित पीरियड रोमांस है। फिल्म में प्रभाष अहम किरदार में होंगे। इसके अलावा फिल्म में इमानवी इस्माइल, जया पर्दा और मिथुन चक्रवर्ती नजर आएंगे।

प्रभास वर्कफ्रंट

'फौजी' के अलावा साउथ अभिनेता प्रभास 'स्पिरिट', 'द राजा साब' के अलावा भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे। 'स्पिरिट' का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं। इस फिल्म में प्रभास एक पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं, 'द राजा साब' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है।

सैफ बेहतर 'कुक' हैं, मैं अंडा भी नहीं उबाल सकती: करीना कपूर खान

बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान का कहना है कि उन्हें और उनके पति सैफ अली खान को घर पर खाना पकाने की आदत पड़ गई है, लेकिन वह (सैफ) उनसे भी बेहतर खाना बनाते हैं।

अभिनेत्री बुधवार को अपनी 'न्यूट्रिशनिस्ट' (पोषण विशेषज्ञ) रुजुता दिवेकर की पुस्तक द कॉमनसेंस डाइट के विमोचन के अवसर पर बोल रही थीं।

दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद घर के बने खाने से बेहतर कुछ नहीं होता। मेरा मतलब है, अब सैफ और मैंने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा, हम इसका भरपूर लुत्फ उठाते हैं, इसलिए हमने इसे अपनी जीवनशैली बना लिया है। ...सैफ बेहतर 'कुक' हैं, यह स्पष्ट है। मैं तो अंडा भी नहीं उबाल सकती।

करीना (44) ने कहा कि वह अपने भोजन को लेकर ज्यादा चयनात्मक नहीं हैं और यहां तक कि उन्हें कई दिनों तक एक ही चीज, जैसे कि खिचड़ी खाने में भी कोई परेशानी नहीं है।

उन्होंने कहा, अगर मैं तीन दिन तक खिचड़ी नहीं खाती तो मुझे वास्तव में इसे खाने की इच्छा होने लगने लगती है... मेरा रसोइया थक जाता है क्योंकि वह (जैसा मैं खाना चाहती हूं) 10-15 दिनों तक एक जैसा खाना बनाता है... मैं हफ्ते में पांच दिन खिचड़ी खाकर खुश रहती हूं। इसमें थोड़ा सा घी डाल देने से मुझे और आनंद आ जाता है।

अभिनेत्री ने यह भी बताया कि कपूर परिवार एक व्यंजन का बहुत शौकीन है।

करीना ने पाया सूप का नाम लेते हुए इसे परिवार की गोल्डन डिश करार दिया।

वक्फ विधेयक अल्पसंख्यकों को तबाह करने के लिए लाया गया : खरगे

नयी दिल्ली : राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वक्फ विधेयक को मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि यह (विधेयक) अल्पसंख्यकों को तबाह करने के लिए लाया गया है। खरगे ने कहा कि देश में ऐसा माहौल बना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों को तंग करने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वह इस विधेयक को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाएं और सरकार इसे वापस ले ले। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने उच्च सदन में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 288 मत आए जबकि विपक्ष में 238 मत। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि इसमें खामियां और कमियां हैं तथा सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। खरगे ने कहा कि ''जिसकी लाठी, उसकी भैंस'' की स्थिति उचित नहीं है और यह किसी के लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह दान से संबंधित विधेयक है लेकिन इसके प्रावधानों के जरिये अल्पसंख्यकों के हकों को छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पसमांदा और महिलाओं के कल्याण की बात तो करती है, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग के आवंटन में हर साल कटौती की जा रही है।

सरकार अच्छे उद्देश्य के साथ लायी है वक्फ संशोधन विधेयक : पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा

राज्यसभा में बृहस्पतिवार को जनता दल (एस) नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने कहा कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक एक अच्छे उद्देश्य से लेकर आयी है तथा दानदाताओं की संपत्ति का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। उच्च सदन में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने कहा कि वह इस विधेयक को लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि दानदाताओं की संपत्ति का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए या उसे भूमि माफिया के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए।

लोकसभा में बृहस्पतिवार को पांच घंटे चला शून्यकाल, 202 सांसदों ने रखी अपनी बात

लोकसभा में बृहस्पतिवार को पांच घंटे से अधिक समय तक शून्यकाल चला, जिस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद अनुराग ठाकुर समेत 202 सांसदों ने अलग-अलग विषयों पर अपनी बात रखी। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल से लोकसभा में शून्यकाल का समय बढ़ाया गया ताकि जन प्रतिनिधियों को संसद में अपने क्षेत्र की बात रखने का पूरा अवसर मिल सके।

अलग रह रहे पति-पत्नी अपने अहंकार की तुष्टि के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं : उच्च न्यायालय

मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि वैवाहिक विवादों में उलझे माता-पिता अपने अहं की तुष्टि के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। न्यायालय ने एक महिला की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसने बच्चे के जन्म संबंधी रिकॉर्ड में माता-पिता के रूप में केवल अपना नाम दर्ज करने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति मंगेश पाटिल और न्यायमूर्ति वाई जी खोबरागड़े ने 28 मार्च के आदेश में कहा कि माता-पिता में से कोई भी अपने बच्चे के जन्म रिकॉर्ड के संबंध में किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह याचिका इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार एक वैवाहिक विवाद कई मुकदमों का कारण बनता है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि यह याचिका न्यायिक प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है तथा न्यायालय के बहुमूल्य समय की बर्बादी है।

रक्षा मंत्रालय ने तेलंगाना में आदिलाबाद हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी

हैदराबाद : रक्षा मंत्रालय ने निजाम काल में स्थापित हुए आदिलाबाद हवाई अड्डे पर नागरिक विमान परिचालन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तेलंगाना सरकार को लिखे पत्र में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) भविष्य में उस स्थान पर एक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापित करने की योजना बना रही है। पत्र में कहा गया है, ''हालांकि, भारतीय वायुसेना ने अनुरोध पर विचार किया है और आदिलाबाद हवाई क्षेत्र से नागरिक विमान परिचालन के लिए तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है।''

हम भारत के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए उत्सुक हैं: जर्मनी के राजदूत

नयी दिल्ली : जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि उनके देश में जल्द ही नई सरकार गठित होगी, लेकिन भारत के साथ राजनीतिक संबंधों के मामले में ''निरंतरता'' बनी रहेगी। बुधवार रात यहां एक कार्यक्रम के इतर 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में उन्होंने कहा, ''हम आने वाले वर्षों में अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की उम्मीद कर रहे हैं।'' राजदूत ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर इस वर्ष के अंत तक यूरोपीय संघ-भारत के बीच वार्ता की भी उम्मीद जतायी। यह पूछे जाने पर कि यूरोपीय संघ-भारत एफटीए की संभावनाओं को जर्मनी किस तरह देखता है, एकरमैन ने कहा, ''हमें लगता है कि यह भारत में हमारे व्यापार के लिए एक बड़ा बदलाव है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप अधिक निवेश देखेंगे।'' एकरमैन ने कहा, ''मुझे पूरा विश्वास है कि जर्मनी और भारत तथा यूरोप और भारत के बीच यह अत्यंत गहन सहयोग जारी रहेगा।'' द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''कुछ सप्ताह में हमारी नई सरकार गठित हो जाएगी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भारत के साथ राजनीतिक संबंधों में निरंतरता बरकरार रहेगी।''

न्यूज इन ब्रीफ

महाराष्ट्र के सोलापुर में भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया, कोई हताहत नहीं

सोलापुर : महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार को 2.6 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने यह जानकारी दी। जिले के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के कारण किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि भूकंप का झटका पूर्वाह्न 11 बजकर 22 मिनट पर दर्ज किया गया, जिसका केंद्र दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्र में स्थित इस जिले के संगोला के पास पांच किलोमीटर की गहराई में था।

नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रही चीन की महिला को वापस भेजा गया

चंपावत (उत्तराखंड) : बिना वीजा के संन्यासिनी के भेष में नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रही चीन की एक महिला को एसएसबी की मदद से पकड़ लिया गया और पूछताछ के बाद उसे वापस नेपाल भेज दिया गया। चंपावत के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने यहां बताया कि सशस्त्र सीमा बल(एसएसबी) के एक दल को गश्त के दौरान बुधवार रात दो बजे संन्यासिनी के भेष में एक महिला नेपाल की तरफ से भारतीय सीमा की ओर आती दिखी। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट के आधार पर उसकी पहचान चीनी नागरिक यांग क्यूहान (30) के रूप में हुई। गणपति ने बताया कि क्यूहान ने सिर पर ओम नम: शिवाय लिखा साफा पहना हुआ था जबकि उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। वह सफेद धोती पहने हुए थी। वैधानिक कार्रवाई के बाद महिला को भारतीय अप्रवासन विभाग को सौंप दिया गया जहां से उसे नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जरिए वापस नेपाल भेज दिया गया।

विमानन कंपनियों को इस साल 25 मार्च तक बम की झूठी खबरों की 24 कॉल मिलीं : सरकार

नयी दिल्ली : सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद को बताया कि इस साल 25 मार्च तक विमानन कंपनियों को बम की झूठी खबरों की 24 कॉल मिलीं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के आंकड़ों का हवाला देते हुए, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि वर्ष 2022 से 25 मार्च, 2025 तक विमानन कंपनियों को बम होने की 836 झूठी खबरें मिली हैं। वर्ष 2022 में, ऐसी कॉल की संख्या 13 थी और वर्ष 2023 में यह संख्या बढ़कर 71 हो गई। पिछले साल, 728 ऐसी कॉल आई थीं और इस साल 25 मार्च तक यह संख्या 24 थी। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में बम की ऐसी धमकी देने के लिए 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़: हटाए गए डीआरएम को पटियाला में नयी तैनाती मिली

नयी दिल्ली : नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद दिल्ली डिवीजन से मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) के पद से हटाए गए सुखविंदर सिंह को 'पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स' में स्थानांतरित कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा एक अप्रैल को जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि सुखविंदर सिंह को डीआरएम/डीएलआई के पद से मुक्त करने के बाद पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (पीएलडब्ल्यू) में स्थानांतरित किया जाए और इसी कैडर में तैनात किया जाएं। रेल मंत्रालय ने नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की भगदड़ की घटना में 18 यात्रियों की मौत हो जाने के बाद चार मार्च को चार अलग-अलग आदेश जारी करके पांच अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया था। उनमें सिंह समेत चार अधिकारियों को रेलवे के विभिन्न विभागों और मंडलों में नयी नियुक्ति मिली है।

महाराष्ट्र : मराठी नहीं बोलने पर सरकारी बैंक के दो प्रबंधकों को मनसे कार्यकर्ताओं ने धमकाया

पुणे : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य के ठाणे और पुणे जिलों में दो अलग-अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधकों को ग्राहकों से मराठी में बात नहीं करने पर धमकाए जाने का मामला सामने आया है। ये अलग-अलग घटनाएं बुधवार को ठाणे के अंबरनाथ शहर और पुणे के लोनावाला में घटित हुईं। इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि लोनावाला में पुलिस ने मनसे के एक कार्यकर्ता के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया है, क्योंकि उसने बैंक प्रबंधक के साथ बातचीत के दौरान बैंक के एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया था। वीडियो में मनसे के कार्यकर्ता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की

लोनावाला शाखा के प्रबंधक से मराठी भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर बहस करते नजर आ रहे हैं। मनसे कार्यकर्ताओं ने बैंक के प्रबंधक को स्थानीय भाषा में बात करने की चेतावनी भी दी। वहीं, जब बैंक का एक मराठी भाषी कर्मचारी हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो कुछ पार्टी कार्यकर्ता उसे थप्पड़ मारते और केबिन से बाहर धकेलते हुए दिखाई देते हैं। लोनावाला थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुहास जगताप ने कहा, ''हमने बैंक के कर्मचारी को थप्पड़ मारने के आरोप में मनसे के एक कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बैंक ने भी शिकायत दर्ज कराई है और हम मामले की जांच कर रहे हैं।''

माझी ने 5,770 करोड़ रुपये की 14 औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया

भुवनेश्वर : ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बृहस्पतिवार को 13 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 5,770 करोड़ रुपये के संचयी निवेश वाली एक इकाई का उद्घाटन किया, जिससे 37,030 से अधिक लोगों के लिए नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। माझी ने खुर्दा जिले के मालीपाड़ा में 624 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित वरुण बेवरेजेज लिमिटेड का उद्घाटन किया। उन्होंने 13 अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी, जो सभी खुर्दा जिले में स्थित हैं। माझी ने कहा कि यह कार्यक्रम उत्कर्ष ओडिशा - 'मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025' के पूरा होने के 60 दिन के भीतर आयोजित किया गया। उद्योग जगत के नेताओं और राज्य के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में शुरू की गईं ये परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, परिधान और तकनीकी वस्त्र, यांत्रिक और विद्युत पूंजीगत सामान सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं। परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद माझी ने कहा, ''ये परियोजनाएं औद्योगिक इकाइयों से कहीं अधिक हैं - ये हमारे राज्य के विकास की नींव हैं, हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजनकर्ता हैं और 'समृद्ध' ओडिशा की हमारी यात्रा में मील की पत्थर हैं। हम एक ऐसे ओडिशा का निर्माण कर रहे हैं जो उत्पादक, समावेशी, टिकाऊ और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हो।''

सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड मिलेगा; पंजीकरण जल्द शुरू होगा

नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना सिर्फ उन महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी, जो राष्ट्रीय राजधानी में रहती हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के लिए 'स्मार्ट कार्ड' जारी करने की कवायद शुरू करने जा रहा है, जो 'आजीवन' वैध रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड पाने की इच्छुक महिलाओं के लिए जल्द ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगी।

मुस्लिम संगठन ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने का किया स्वागत

बरेली (उप्र) : 'ऑल इंडिया मुस्लिम जमात' के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने का बृहस्पतिवार को स्वागत करते हुए उम्मीद जतायी कि इससे देश में गरीब मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। रजवी ने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने पर उम्मीद जगी है कि देश में कुछ अच्छा काम होगा और गरीब मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में 'जबरदस्त इंकलाब' आएगा। उन्होंने कहा कि वह उन सभी लोकसभा सदस्यों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया है। बरेलवी मसलक के मौलाना रजवी ने कहा कि वह केन्द्र सरकार को भी मुबारकबाद देते हैं कि उसने यह विधेयक पारित करवाकर अच्छा कदम उठाया है और ''बुराई के खात्मे'' के लिए अच्छी पहल की है। उन्होंने आरोप लगाया, ''वक्फ बोर्ड पर काबिज लोग भू-माफिया से मिलकर करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे। वक्फ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वक्फ की मंशा यही थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, लेकिन वह आमदनी कुछ लोगों की जेब में जाती थी।'' लोकसभा ने बुधवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच और साढ़े 10 घंटे से अधिक समय तक चर्चा करने के बाद देर रात करीब दो बजे वक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को पारित किया।

मुगलों के नाम वाले मार्गों का नामकरण राणा सांगा, शिवाजी जैसे महापुरुषों के नाम पर हो: भाजपा सांसद

नयी दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद राजकुमार चाहर ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुगल शासकों के नाम वाले मार्गों का नामकरण राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों के नाम पर किये जाने की मांग की। चाहर ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कहा, ''दिल्ली में लुटियंस क्षेत्र में बाबर लेन, तुगलक रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड जैसे अनेक मार्ग हैं जिनके ये नाम मुगल आक्रांताओं और लुटेरों के नाम पर हैं जो कांग्रेस सरकार के समय से हैं।'' उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि इन सड़कों के नाम राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, महाराज सूरजमल और शिवाजी महाराज आदि महापुरुषों के नाम पर रखे जाएं जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी।

सीमा शुल्क विभाग हवाई यात्रियों के पुराने आभूषणों को अनावश्यक रूप से जब्त न करे: उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि सफर के समय यात्री द्वारा पहने जाने वाले आभूषण सहित यात्रियों के पुराने और निजी आभूषण को हवाई अड्डों पर अनावश्यक रूप से जब्त नहीं किया जाए और उन्हें प्रताड़ित भी नहीं किया जाए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ को सीमा शुल्क विभाग ने सूचित किया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श किया जा रहा है तथा सामान नियम में संशोधन के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। इसके बाद, पीठ ने यह निर्देश पारित किया। अदालत 30 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई

कर रही थी, जिसमें सीमा शुल्क विभाग द्वारा भारत आने वाले देश के नागरिकों और विदेशी मूल के पर्यटकों के सामान को जब्त करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। पीठ ने कहा, ''चूंकि सीबीआईसी और सीमा शुल्क विभाग अब सामान नियमों में संशोधन करने और इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए और समय का अनुरोध कर रहे हैं, इसलिए सीमा शुल्क विभाग अपने सभी अधिकारियों को इस स्थिति से अवगत कराए।'' पीठ ने कहा, ''सीमा शुल्क अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यहां तक कि भारतीय यात्रियों के पुराने आभूषण, यात्रा के दौरान उनके द्वारा पहने जाने वाले निजी आभूषण या इस्तेमाल आभूषणों को भी अनावश्यक रूप से जब्त न किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो।'' पीठ ने यह भी कहा कि अगर अगली सुनवाई की तारीख तक सामान नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता है तो 19 मई तक एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) रिकॉर्ड पर रखी जानी चाहिए, जिसका नियमों में संशोधन होने तक सीमा शुल्क विभाग द्वारा पालन किया जाएगा।

कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव, जौहरी साहिल 40 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी में शामिल: डीआरआई

बेंगलुरु : जौहरी साहिल सकारिया जैन ने कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रन्या उर्फ रन्या राव को तस्करी के 49.6 किलोग्राम सोने को खपाने में सहायता की। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने यह जानकारी दी। इस सोने की कीमत 40.14 करोड़ रुपये आंकी गई है। डीआरआई की रिमांड नोट के अनुसार, जैन ने न केवल इस अवैध लेनदेन को अंजाम देने में मदद की, बल्कि तस्करी की कमाई का हवाला के जरिए अंतरण करने में भी सहयोग दिया। जैन को सोने की तस्करी में रन्या की मदद करने को लेकर 26 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उसे सात अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डीआरआई ने कहा, ''ऐसा प्रतीत होता है कि साहिल जैन ने रन्या की लगभग 49.6 किलोग्राम सोने (कीमत 40,13,59,374 रुपये) को खपाने में सहायता की। साहिल ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने हवाला के जरिए दुबई में 38,39,97,000 रुपये और बेंगलुरु में 1,73,61,787 रुपये की धनराशि भेजने में रन्या की मदद की थी।। डीआरआई ने कहा कि जैन ने प्रत्येक लेनदेन के लिए 55,000 रुपये का कमीशन लेने की बात स्वीकार की है। डीआरआई ने कहा,''साहिल सकारिया जैन के दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप से मिले सबूतों से यह स्पष्ट होता है कि उसने रन्या द्वारा भारत में भारत में सोने की तस्करी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एजेंसी के अनुसार, जनवरी 2025 में जैन ने रन्या को 14.568 किलोग्राम सोने (मूल्य 11.56 करोड़ रुपये) को खपाने और 11.01 करोड़ रुपये दुबई में हवाला के माध्यम से भेजने में मदद की। इसके अलावा, उसने बेंगलुरु में 55 लाख रुपये स्थानांतरित करने की बात स्वीकार की। फरवरी में, जैन ने रन्या को 13.433 किलोग्राम सोने (मूल्य 11.81 करोड़ रुपये) को खपाने में मदद की।

न्यू इंडिया सहकारी बैंक मामला: पुलिस को 168 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी मिली

मुंबई : नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद मुंबई में ऐसे पहले मामले में एक अदालत ने पुलिस को न्यू इंडिया सहकारी बैंक में कथित गबन के सिलसिले में पांच आरोपियों की 167.85 करोड़ रुपये की 21 संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दी है। एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बुधवार को मजिस्ट्रेटी अदालत से मंजूरी मिलने के बाद कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी।

तेलंगाना में पेड़ों की कटाई का मामला : न्यायालय ने अगले आदेश तक किसी भी गतिविधि पर रोक लगायी

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना सरकार से हैदराबाद विश्वविद्यालय के बगल में स्थित भूखंड पर लगे बड़े वृक्षों को हटाने की ''मजबूरी'' के बारे में स्पष्टीकरण मांगा तथा अगले आदेश तक किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी। राज्य में पेड़ों की कटाई को ''बहुत गंभीर मामला'' बताते हुए न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा उसके समक्ष पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट ''चिंताजनक तस्वीर'' पेश करती है। रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। पीठ ने कहा, ''हम निर्देश देते हैं कि अगले आदेश तक, पहले से मौजूद पेड़ों के संरक्षण के अलावा, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि राज्य द्वारा नहीं की जाएगी।'' पीठ ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से पूछा कि राज्य द्वारा पेड़ों को हटाने समेत विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने की तत्काल इतनी क्या मजबूरी है। मुख्य सचिव को यह भी बताने का निर्देश दिया गया कि क्या राज्य ने ऐसी गतिविधियों के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि अगर उसे राज्य की ओर से कोई चूक मिली तो वह मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पीठ ने कहा, ''उन्हें (मुख्य सचिव) झील के पास उसी स्थान पर बनाई गई अस्थायी जेल में भेजा जाएगा।'' पीठ ने पूछा कि क्या पेड़ों को काटने के लिए वन प्राधिकरण या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमति ली गई थी। इसने कहा कि यदि राज्य के अधिकारी

किसी भी निर्देश का उल्लंघन करते पाए गए, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य के मुख्य सचिव पर होगी। अदालत ने काटे गए पेड़ों की स्थिति के बारे में भी पूछताछ की। पीठ ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त एक समिति को संबंधित स्थान का दौरा करने और 16 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की। इससे पहले दिन में, न्यायालय ने हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटी 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई मामले का संज्ञान लेते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र का तत्काल दौरा करने का निर्देश दिया। पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को अपराह्न 3:30 बजे तक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की सुनवाई अपराह्न 3:45 बजे होगी। इस मुद्दे को वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने पीठ के समक्ष उठाया, जो पर्यावरण से संबंधित मामले में न्यायमित्र के रूप में उच्चतम न्यायालय की सहायता कर रहे हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि न्यायमित्र कई समाचार रिपोर्ट को उसके संज्ञान में लाए हैं, जिनमें वहां बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का दावा किया गया है। पीठ ने कहा, ''इसलिए, हम तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश देते हैं कि वह तत्काल संबंधित स्थल का दौरा करें और आज अपराह्न 3:30 बजे तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।'' पीठ ने उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वह उसके आदेश को तत्काल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को सूचित करें, जो तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। पीठ को बताया गया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय भी इसी मामले पर सुनवाई कर रहा है। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा, ''हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम तेलंगाना उच्च न्यायालय में जारी कार्यवाही पर रोक नहीं लगा रहे हैं।'' हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय परिसर से सटी 400 एकड़ जमीन को विकसित करने की राज्य सरकार की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य की कांग्रेस सरकार को इस संबंध में सभी कार्य तीन अप्रैल तक रोकने का निर्देश दिया है।

सशस्त्र बलों को 'गतिशील परिप्रेक्ष्य योजना' तैयार करनी चाहिए: राजनाथ

नयी दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सशस्त्र बलों को वर्तमान गतिशील भू-रणनीतिक परिवर्तनों और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ''गतिशील परिप्रेक्ष्य योजना'' तैयार करनी चाहिए। सिंह ने यहां एक से चार अप्रैल तक शीर्ष सैन्य कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सशस्त्र बलों को भविष्य के लिए तैयार करने को जब भी आवश्यक हो, सैद्धांतिक बदलाव किए जाने चाहिए। सिंह ने कहा, ''सैन्य कमांडर सम्मेलन जैसे मंचों पर वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो

तो मध्यावधि समीक्षा और संशोधन के साथ उन्हें तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए। राष्ट्र को अपनी सेना पर गर्व है और सरकार सुधारों एवं क्षमता आधुनिकीकरण के मार्ग पर सेना को आगे बढ़ने में सहायता करने को प्रतिबद्ध है।'' उन्होंने कहा कि 'हाइब्रिड' युद्ध सहित अपरंपरागत और असममित युद्ध ''भविष्य के पारंपरिक युद्धों का हिस्सा होंगे''। सिंह ने वर्तमान भू-रणनीतिक अनिश्चितताओं और जटिल विश्व स्थिति पर जोर दिया, जिसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर सभी पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व ''एक दूसरे से जुड़ा हुआ विश्व है'' और ऐसी घटनाएं चाहे पड़ोस में हों या दूर के देशों में, सभी को प्रभावित करेंगी। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि सम्मेलन के दौरान सेना के शीर्ष नेतृत्व ने मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य, सीमाओं और भीतरी इलाकों की स्थिति तथा वर्तमान सुरक्षा तंत्र के समक्ष चुनौतियों के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया। सिंह ने रेखांकित किया कि वर्तमान गतिशील भू-रणनीतिक और जारी वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यों तथा अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, ''सशस्त्र बलों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों चुनौतियों का समाधान करते हुए एक गतिशील परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करनी चाहिए।''

कोलकाता ने हैदराबाद को 80 रन से हराया

वरुण-वैंभव को मिले तीन-तीन विकेट

कोलकाता : वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को 120 पर रोककर 80 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह हैदराबाद की आईपीएल में सबसे बड़ी हार है। गुरुवार को कोलकाता के ईडेन गार्डंस में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गत विजेता टीम ने 20 ओवर में छह विकेट खोकर 200 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद 16.4 ओवर में ही ऑलआउट हो गई। इस तरह केकेआर ने एक बार फिर हैदराबाद को पटखनी दी। इससे पहले कोलकाता ने हैदराबाद को हराकर आईपीएल 2024 का खिताब जीता था। पैट कमिंस के नेतृत्व वाली टीम ने इस सत्र की शुरुआत जीत के साथ की थी। उन्होंने अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स को 44 रन से हराया था। इसके बाद उन्हें लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता से मिली हार के बाद सनराइजर्स अंक तालिका में 10वें पायदान पर पहुंच गई। उनका नेट रन रेट -1.612 हो गया। वहीं, केकेआर चार मैचों में दो जीत के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई। उनके खाते में चार अंक और नेट रन रेट 0.070 का हो गया है।

201 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद के बल्लेबाजों ने निर-ाशाजनक प्रदर्शन किया। उनकी तरह से हेनरिक क्लासेन ने सर्वाधिक 33 रनों की पारी खेली। उनके अलावा कामिंदु मेंडिस ने 27, नीतीश कुमार रेड्डी ने 19 और पैट कमिंस ने 14 रन बनाए। वहीं, छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। कोलकाता के लिए वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने तीन-तीन विकेट झटके जबकि आंद्रे रसेल ने दो विकेट चटकाए। इसके अलावा हर्षित राणा और सुनील नरेन को एक-एक सफलता मिली।

निजी कारणों से आईपीएल छोड़कर स्वदेश लौटे रबाडा

नयी दिल्ली : दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा निजी कारणों से आईपीएल छोड़कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। उनकी टीम गुजरात टाइटंस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। टाइटंस ने यह नहीं बताया कि रबाडा कब तक लौटेंगे। अभी तक उन्होंने दो ही मैच खेले हैं। गुजरात टीम ने एक बयान में कहा, 'कैगिसो रबाडा कुछ महत्वपूर्ण निजी मसले से निपटने के लिये दक्षिण अफ्रीका लौट गए हैं।' रबाडा ने पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक एक विकेट लिया था। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ बुधवार को बेंगलुरू में खेले गए मैच में टीम में जगह नहीं दी गई। रबाडा की जगह अरशद खान को उतारा गया जिन्होंने विराट कोहली का कीमती विकेट लिया।

मुंबई और लखनऊ के बीच मैच में रोहित और पंत पर रहेगी निगाह

लखनऊ : मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में शुक्रवार को यहां जब आमने सामने होंगी तो सभी की निगाह रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के प्रदर्शन पर टिकी रहेगी। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का इस सत्र में अभी तक प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है तथा तीन मैच में उसके केवल दो अंक हैं। भारतीय कप्तान रोहित की खराब फॉर्म मुंबई के लिए चिंता का विषय है। यही बात लखनऊ के कप्तान पंत पर भी लागू होती है जो रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन दोनों प्रमुख बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन का असर परिणाम पर साफ नजर आ रहा है। इन दोनों टीमों ने अभी तक तीन में से केवल एक मैच जीता है और ऐसे में शुक्रवार को होने वाले मैच में जो टीम परिस्थितियों से बेहतर सामंजस्य बिठाएगी, उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। यही नहीं इस बार क्यूरेटर घरेलू टीमों के अनुकूल पिच तैयार नहीं कर रहे हैं जिस पर कुछ फ्रेंचाइजी के कोच और खिलाड़ियों ने खुलकर नाराजगी व्यक्त की है। ऐसे में पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम की जीत की संभावना बढ़ जाएगी। मुंबई के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की चोट भी चिंता का विषय है। बुमराह कब तक वापसी करेंगे इसको लेकर हार्दिक पंड्या की अगुवाई वाली टीम ने चुप्पी साध रखी है। बुमराह की जगह लेना आसान नहीं है लेकिन बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अश्वनी कुमार ने पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके मुंबई की टीम में आशा की नई किरण जगाई है। अश्वनी कुमार ने इस मैच में 24 रन देकर चार विकेट लिए थे। पंजाब के रहने वाले इस 23 वर्षीय तेज गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट में केवल चार टी20 मैच खेलने के बाद मुंबई की तरफ से आईपीएल में पदार्पण करते हुए शानदार प्रदर्शन किया तथा अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल जैसे बल्लेबाजों को आउट किया।

सूर्यकुमार मुंबई को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा: एमसीए

मुंबई : मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने गुरुवार को उन खबरों का खंडन किया कि सूर्यकुमार यादव अपने कुछ साथियों के साथ आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र के लिए गोवा जाने की योजना बना रहे हैं। एमसीए ने कहा कि भारत का टी20 कप्तान खेल के प्रत्येक प्रारूप में मुंबई का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुंबई के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रणजी टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों के साथ कथित मतभेदों के कारण पहले ही मुंबई से गोवा जाने की घोषणा कर चुके हैं। जायसवाल हालांकि तभी गोवा की टीम से जुड़ पाएंगे जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अपनी अंतर-राज्य स्थानांतरण विंडो खोलेगा। बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सूर्यकुमार अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली मुंबई रणजी टीम छोड़ सकते हैं। असल में सूर्यकुमार ने खुद ही अपने एक्स हैंडल पर इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। एमसीए सचिव अभय हदाप ने एक बयान में कहा, 'मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) को सूर्यकुमार यादव के कुछ अन्य खिलाड़ियों के साथ गोवा की टीम से जुड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों की जानकारी है।'

दूसरे संयुक्त राष्ट्र खेलों का सह आयोजक है भारत, योग और शतरंज में करेगा अगुवाई

संयुक्त राष्ट्र : भारत खेलों के माध्यम से कूटनीति और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे दूसरे संयुक्त राष्ट्र खेलों का सह आयोजक है जिसमें वह योग और शतरंज जैसे खेलों में अगुवाई करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथनेनी हरीश ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'दूसरे संयुक्त राष्ट्र खेलों के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। सह आयोजक के रूप में, भारत शतरंज और योग में अग्रणी भूमिका निभाएगा।' हरीश ने कह कि संयुक्त राष्ट्र खेल एकता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना का उत्सव हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि अगली बार इन खेलों में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय टीम को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं।' संयुक्त राष्ट्र खेल अप्रैल-मई 2025 में आयोजित किए जाएंगे।

ट्रंप ने भारत पर 27 प्रतिशत का शुल्क लगाया, सरकार कर रही है प्रभाव का आकलन

वाशिंगटन/नयी दिल्ली : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अपने उत्पादों का निर्यात करने वाले करीब 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगा दिया है। इसी निर्णय के तहत भारत पर 27 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाया गया है। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में झींगा से लेकर इस्पात तक के उत्पादों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। अमेरिका ने भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 27 प्रतिशत का भारी शुल्क लगा दिया है। हालांकि, फार्मास्युटिकल्स, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और कुछ खनिज पदार्थ को इससे छूट दी गई है। ये उत्पाद अमेरिका में उपलब्ध नहीं हैं। अमेरिका ने भारत को अनुचित व्यापार व्यवहार का 'सबसे अधिक दुरुपयोग' करने वाला देश बताते हुए उसपर शुल्क लगाया है। अमेरिका को झींगा, कालीन, चिकित्सा उपकरण और सोने के आभूषण जैसे उत्पादों का निर्यात प्रभावित होगा। दूसरी ओर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और फार्मा के निर्यात को उसके प्रतिस्पर्धी देशों पर बढ़त मिलेगी। ऊर्जा को शुल्क से छूट देने का मतलब यह भी होगा कि भारत अमेरिका को पेट्रोल जैसे ईंधन का निर्यात जारी रख सकता है। शुल्क से छूट प्राप्त सामान भारत से अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात का लगभग 25 प्रतिशत है। भारत सरकार ने इस शुल्क पर सतर्क प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वह घोषणाओं के 'प्रभावों की सावधानीपूर्वक जांच कर रही है' तथा अमेरिकी व्यापार नीति में इस फैसले के कारण उत्पन्न होने वाले अवसरों का भी अध्ययन करेगी। ट्रंप ने सभी व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त मूल्यानुसार शुल्क लगाने की घोषणा की। भारत पर 10 प्रतिशत का मूल शुल्क पांच अप्रैल से और 27 प्रतिशत शुल्क नौ अप्रैल से प्रभावी होगा। यह 27 प्रतिशत शुल्क, अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय उत्पादों पर वर्तमान में लागू किसी भी शुल्क के अतिरिक्त होगा। हालांकि, इस कदम से अमेरिका को भारत की कुछ वस्तुओं के निर्यात पर असर पड़ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। इनमें बांग्लादेश (37 प्रतिशत), चीन (54 प्रतिशत), वियतनाम (46 प्रतिशत) और थाइलैंड (36 प्रतिशत) शामिल हैं, जिन्हें बढ़े हुए शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता से शुल्क प्रभाव कम होने की उम्मीद: एसीएमए

भारतीय वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संघ (एसीएमए) ने बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क आदेशों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी और एक संतुलित समाधान निकलेगा जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा, हालांकि, अमेरिका में 25 प्रतिशत आयात शुल्क के अधीन आने वाले वाहन कलपुर्जों की विस्तृत सूची का इंतजार है।

भारत के लिए वैश्विक व्यापार और विनिर्माण में स्थिति मजबूत करने का अवसर: जीटीआरआई

आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीअ-रआई) ने कहा कि अमेरिका की ओर से चीन, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और बांग्लादेश सहित कई एशियाई देशों पर उच्च जवाबी शुल्क लगाए जाने से भारत के लिए वैश्विक व्यापार और विनिर्माण में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर पैदा हुआ है। जीटीआरआई ने कहा कि दवा, सेमीकंडक्टर, तांबा जैसी आवश्यक एवं रणनीतिक वस्तुओं और तेल, गैस, कोयला व तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलए-नजी) जैसे ऊर्जा उत्पादों को अमेरिका ने बुधवार को घोषित 27 प्रतिशत आयात शुल्क में छूट दी गई है जिससे इन क्षेत्रों में भारत के लिए नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

अमेरिकी जवाबी शुल्क से भारत के जीडीपी पर 0.50 प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा : विशेषज्ञ

नयी दिल्ली : डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा घोषित जवाबी शुल्क से भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 0.50 प्रतिशत तक घटकर छह प्रतिशत रह सकती है। साथ ही इससे अमेरिका को देश के निर्यात में दो से तीन प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। वित्तीय सेवा कंपनी ईवाई के मुख्य नीति सलाहकार डी के श्रीवास्तव ने कहा, भारत की जीडीपी वृद्धि पर अधिकतम प्रतिकूल प्रभाव 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। हमारे पहले के अनुमान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.5 प्रतिशत था, जो बिना किसी प्रतिक्रिया के छह प्रतिशत तक कम हो सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की भारत में शोध प्रमुख अनुभूति सहाय ने कहा, ''हमारे विचार से अमेरिका को भारतीय निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क वृद्धि (छूट प्राप्त वस्तुओं पर विचार करने के बाद) से भारत की जीडीपी पर 0.35-0.40 प्रतिशत का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

अमेरिकी जवाबी शुल्क भारत के कपड़ा उद्योग के लिए 'अनुकूल स्थति' : रेमंड ग्रुप

नयी दिल्ली : अमेरिकी के जवाबी शुल्क ने भारत को कपड़ा निर्यात के मामले में 'अनुकूल स्थिति' में ला दिया है, क्योंकि देश को चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे अन्य परिधान निर्यातक देशों की तुलना में सापेक्ष लागत का लाभ होगा। रेमंड ग्रुप के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) अमित अग्रवाल ने पीटीआई-भाषा को बताया, 'अमेरिका द्वारा घोषित जवाबी शुल्क स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि भारत चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे अन्य परिधान निर्यातक देशों की तुलना में अत्यधिक अनुकूल स्थिति में है। हमें पहले से ही अमेरिकी ग्राहकों से क्षमता उपलब्धता के बारे में पूछताछ मिलनी शुरू हो गई है।'

पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) की महानिदेशक पूनम गुप्ता को तीन साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से तीन साल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए है। माइकल देबव्रत पात्रा के जनवरी में पद छोड़ने के बाद आरबीआई में डिप्टी गवर्नर का पद खाली हो गया था। वह मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य थे। गुप्ता की नियुक्ति के साथ ही अब डिप्टी गवर्नर के सभी चार पद भर गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक एमपीसी बैठक सात से नौ अप्रैल को होनी है।

उप्र को एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में गन्ना विकास विभाग देगा बड़ा योगदान

लखनऊ : उत्तर प्रदेश को एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण यो-गदान देने के प्रयास में, राज्य के गन्ना विकास विभाग ने 2025-26 के लिए 1,41,846 करोड़ रुपये के जीवीओ (सकल उत्पादन मूल्य) का लक्ष्य रखा है। एक बयान के अनुसार गन्ना विकास विभाग ने अपनी वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना प्रस्तुत की है। इसमें विभाग का लक्ष्य राज्य सरकार पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देना है।

सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने की बढ़ती लागत की वजह से दाम बढ़ा रही हैं कार कंपनियां

नयी दिल्ली : अनिवार्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे माल की बढ़ती लागत के साथ-साथ सभी संस्करणों में छह एयरबैग जैसी सुविधाओं के लिए उपभोक्ताओं की बढ़ती पसंद के कारण कार विनिर्माता सुस्त मांग के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। उद्योग जगत के दिग्गजों ने यह बात कही है। अग्रणी ब्रांड मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को आठ अप्रैल से विभिन्न मॉडल की कीमतों में 2,500-62,000 रुपये तक की वृद्धि करने की घो-षणा की है। इस साल यह उसकी दूसरी वृद्धि है। मारुति सुजुकी इंडिया ने इससे पहले एक फरवरी से विभिन्न मॉडल की कीमतों में 32,500 रुपये तक की वृद्धि की थी। इसी तरह, बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने इस महीने से चुनिंदा मॉडल पर तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। हुंदै, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया और होंडा कार्स ने भी अप्रैल से वाहनों की कीमतें बढ़ाने की योजना की घो-षणा की है। पूरे यात्री वाहन बाजार में सुस्ती के बावजूद कीमतों में वृद्धि करने के सवाल पर मारुति सुजुकी इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, कीमतों में वृद्धि पूरी तरह से नियामकीय बदलावों के कारण कच्चे माल की लागत के चलते की गई है। आंशिक रूप से ऐसी लागत का बोझ ग्राहकों पर डाला गया है। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विक्रम पावाह ने कहा, हम हर तिमाही में इसकी समीक्षा करते हैं और विनिमय दर तथा कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण हम कीमतों में संशोधन करते हैं। हमने अप्रैल में भी कुछ विशेष मॉडल पर तीन प्रतिशत तक की मामूली मूल्यवृद्धि की थी। उद्योग के जानकारों के अनुसार, 3-पॉइंट ईएलआर सीट बेल्ट और सामान रखने के लिए पीछे की सीटों को मजबूत बनाने जैसी सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण भारत में यात्री वाहनों की लागत बढ़ गई है। उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, इसके अलावा, विभिन्न संस्करणों में छह एयरबैग जैसे अधिक सुरक्षा खूबियों की उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग के कारण भी इसकी लागत बढ़ गई है।

देश के 2030 तक 7,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में प्रौद्योगिकी क्षेत्र महत्वपूर्ण: नैसकॉम

नयी दिल्ली : प्रौद्योगिकी कंपनियों के शीर्ष संगठन नैसकॉम ने कहा है कि भारत 2030 तक 7,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रह है। इसमें प्रौद्योगिकी क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 1,000 अरब डॉलर का योगदान देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जिससे घरेलू और वैश्विक दोनों समस्याओं का समाधान करने वाले नवोन्मेष को बढ़ावा मिलेगा। नैसकॉम के अध्यक्ष राजेश नांबियार ने भारत के भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीकी क्षेत्र को विशेष रूप से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवोन्मेष में अगुवा होना होगा। यह स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सहायक होगा। उन्होंने स्टार्टअप महाकुंभ के उद्घाटन के दौरान कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने का देश का दृष्टिकोण न केवल आर्थिक वृद्धि से बल्कि प्रौद्योगिकी नवोन्मेष से भी आकार लेगा। नांबियार ने कहा, 'भारत के लिए 7,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए, मुझे लगता है कि अकेले प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में लगभग 1,000 अरब डॉलर का योगदान करना होगा। इससे नवोन्मेष को बढ़ावा मिलेगा, जो न केवल भारत की समस्या बल्कि वैश्विक समस्याओं को भी हल करेगा।' उन्होंने वैश्विक स्टार्टअप परिदृश्य में भारत की मजबूत स्थिति का जिक्र किया, जिसके साथ देश अब दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है।

न्यूज अपडेट

सोना 200 रुपये की बढ़त के साथ 94,350 रुपये के नए शिखर पर, चांदी 1,000 रुपये टूटी

नयी दिल्ली : आभूषण विक्रेताओं और स्टॉकिस्ट की सतत लिवाली के बीच बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 200 रुपये बढ़कर 94,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है। बुधवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 94,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा था। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 200 रुपये बढ़कर 93,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। हालांकि, चांदी की कीमत बुधवार के बंद स्तर 1,01,500 रुपये प्रति किलोग्राम से 1,000 रुपये टूटकर 1,00,500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। एलकेपी सिक्योरिटीज में उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक जिंस और मुद्रा जतिन त्रिवेदी ने कहा, 'जवाबी शुल्क के प्रभाव से सुबह के सत्र में सोने में शुरुआती तेजी देखी गई, लेकिन जल्द ही कीमतों में मुनाफावसूली का दौर शुरू हो गया।'

ट्रंप की शुल्क घोषणा से सेंसेक्स 322 अंक टूटा, आईटी शेयरों में बिकवाली

मुंबई : स्थानीय शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 322 अंक टूट गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत समेत 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा के बाद सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) शेयरों में बिकवाली तथा वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख से बाजार नुकसान में रहा। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 322.08 अंक यानी 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,295.36 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 809.89 अंक तक लुढ़क गया था। हालांकि, बाद में औषधि शेयरों में तेजी से बाजार नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करने में सफल रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 82.25 अंक यानी 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,250.10 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी एक समय 186.55 अंक तक लुढ़क गया था। अमेरिका ने भारत पर 27 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अमेरिकी वस्तुओं पर भारत उच्च आयात शुल्क वसूलता है, ऐसे में अब देश के व्यापार घाटे को कम करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था।

बीएमडब्ल्यू इंडिया की बिक्री मार्च तिमाही में सात प्रतिशत बढ़कर 3,914 इकाई पर

नयी दिल्ली : जर्मनी की लक्जरी कार विनिर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू की वाहन बिक्री जनवरी-मार्च तिमाही में सालाना आधार पर सात प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,914 इकाई रही। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह उसकी मार्च तिमाही में अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री है और इसमें स्पोर्ट्स और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खंड का प्रमुख योगदान रहा। समूह ने पिछले साल की इसी तिमाही में 3,675 गाड़ियां बेची थीं। समूह 2025 में दहाई अंक में बिक्री वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने कहा कि 2025 की पहली तिमाही में बीएमडब्ल्यू ब्रांड ने 3,764 तो 'मिनी' ने 150 गाड़ियों की बिक्री दर्ज कीं। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विक्रम पावाह ने पीटीआई-भाषा से कहा, यदि आप समग्र बाजार को देखें तो बाजार में कुछ रुझान या अवसर हैं। भले ही नरमी है, फिर भी समग्र बाजार में एसयूवी की मांग बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक कारें लोकप्रिय हैं और समग्र बाजार में उनका प्रदर्शन भी अच्छा है।

आईकॉनिक व्हाइट व्हिस्की ने 344 दिनों में 50 लाख केस बेचकर सफलता की नई ऊंचाई छुई

कोलकाता, समाज्ञा : एलायड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड (एबीडी), भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्पिरिट्स कंपनी और आईकॉनिक व्हाइट इंटरनेशनल ग्रेन व्हिस्की की निर्माता, ने अपने प्रमुख ब्रांड आईकॉनिक व्हाइट व्हिस्की के 50 लाख (5 मिलियन) केस बेचने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह सफलता वित्तीय वर्ष 24-25 में केवल 344 दिनों में प्राप्त की गई, जिससे यह ब्रांड विश्वभर में तेजी से बढ़ते हुए व्हिस्की ब्रांड के रूप में स्थापित हो गया है। सितंबर 2023 में लॉन्च के बाद से, आईकॉनिक व्हाइट व्हिस्की ने प्रीस्टिज एंड अबव सेगमेंट में अपनी पहचान बनाई है, इसकी आधुनिक पैकेजिंग और मजबूत उपभोक्ता मांग के कारण। पहले वित्तीय वर्ष (2022-23) में 3.2 लाख केस बेचे गए, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा 22.7 लाख केस तक पहुंचा। एबीडी के प्रबंध निदेशक आलोक गुप्ता ने कहा, आईकॉनिक का 50 लाख केस पार करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह युवाओं में पसंदीदा व्हिस्की बन चुकी है, और हम इसके वैश्विक विस्तार के लिए आशान्वित हैं। ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें गोल्ड मेडल्स और श्रेष्ठ स्वाद पुरस्कार शामिल हैं, जो इसे प्रीमियम व्हिस्की के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं।

वर्ष 10, पूर्णांक 4196 अंक 006, RNI No WBHIN/2016/66788, सर्वांग प्रकाशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सरोज राय द्वारा 17, बालमुकुन्द मक्कर रोड, 2सरा तल्ला, कोलकाता-700 007 से प्रकाशित। एल. एस. पब्लिकेशन्स प्रा. लि. 4, कैनल वेस्ट रोड, कोलकाता-700 015 से मुद्रित।
सम्पादक- अनिल कुमार राय (पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी), विज्ञापन एवं प्रसार-9874555256/7044444522, ई-मेल news@samagya.in